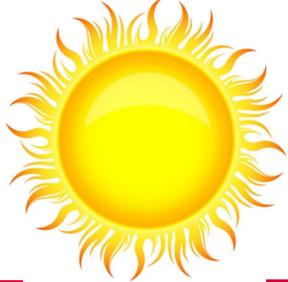


दैनिक दिव्य सांवाद

वर्ष 01 अंक: 49

उज्जैन शुकवार दिनांक 27 मार्च 2026 फालगुन मास शुक्ल पक्ष नवमी संवत् 2083

पृष्ठ: 8 मूल्य :02 रूपये



मौसम आज

तापमान

न्यूनतम - 17 डि.से.

अधिकतम - 37 डि.से.

न्यूज गैलरी

झारखंड में सर्पदंश और कुष्ठ रोग अब अधिसूचित बीमारी घोषित



नई दिल्ली (एजेंसी)। राज्य सरकार ने सर्पदंश और इससे होनेवाली मृत्यु के साथ-साथ कुष्ठ रोग को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। इससे अब इसके मामले सामने आने पर अनिवार्य रूप से इसकी जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी। जिला स्तर पर इसकी जानकारी सिविल सर्जन कार्यालय को दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर अलग-अलग अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में सर्पदंश से होने वाली मौतों के बढ़ते आंकड़ों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त कुष्ठ रोग को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे अधिसूचित रोगों की श्रेणी में सम्मिलित किया है। यह कदम भारत सरकार के नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्लेकबाइट एनवेनोमिंग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिसके तहत वर्ष 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों और दिव्यांगता में 50 प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य है।

मुझे गालियां देकर सरकार में आए, अगले चार साल यही करेंगे; केजरीवाल का भाजपा पर हमला



नई दिल्ली (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फिर से दिल्ली की भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। राजेंद्र नगर विधानसभा के कुछ इलाकों में कई दिनों से पानी न आने की स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही शिकायतों पर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे गालियां दे देकर ही ये लोग सरकार में आए थे और अगले चार साल केवल मुझे गालियां ही देंगे। इनको न सरकार चलानी आती है और न ही इनकी इच्छा है। दिल्लीवाले इनको वोट देकर ठगा महसूस कर रहे हैं। केजरीवाल ने पानी न आने को लेकर एक्स पर की गई राजेंद्र नगर के निवासी की शिकायत को साझा कर कहा कि देखिए, इन लोगों ने कैसे दिल्ली वालों की जिंदगी नर्क बना दी है। इन्होंने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है।

अपराध और माफिया पर दिलाई बर्दाशत नहीं, तत्काल करें कार्रवाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर जनता दर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था पर अपनी जोरो टॉलरेंस नीति को और धार दी। लोगों की समस्या सुनने के दौरान उन्होंने सख्त लहजे में अधिकारियों को संदेश दिया कि अपराध और माफिया पर किसी तरह की ढिलाई या उदासीनता हरगिज बर्दाशत नहीं की जाएगी। इसे लेकर सख्त कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार परिसर में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच पहुंचे और एक-एक कर उनकी समस्याएं सुनीं। सभी का प्रार्थना-पत्र अपने हाथों लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारी को दिया और मौके पर ही निर्देशित करते हुए कहा कि हर



शिकायत का समाधान समयबद्ध, निष्पक्ष और संतोषजनक होना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री समस्या लेकर आए लोगों को यह कहते हुए आश्वासन करते रहे कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सरकार हर समस्या के प्रभावी प्रभावी निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। जमीन कब्जा और दबाई से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री का रुख बेहद आक्रामक रहा। उन्होंने साफ निर्देश दिया कि अगर कोई व्यक्ति गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ

कठोरतम कार्रवाई की जाए। उन्होंने दो टुक कहा कि गरीबों को उजाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनकी संपत्ति पर उनका ही अधिकार सुनिश्चित कराया जाएगा। जनता दर्शन में आए पारिवारिक विवादों के मामलों पर मुख्यमंत्री ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए पहले आपसी संवाद पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि बातचीत से समाधान न निकले, तो विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि न्याय में देरी न हो। आर्थिक तंगी के कारण इलाज में बाधा झेल रहे लोगों को मुख्यमंत्री ने एक बार फिर राहत भरा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रहेगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जरूरतमंदों के इलाज का एस्टीमेट तत्काल तैयार कर शासन को भेजा जाए,

ताकि बिना देरी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने जहां एक ओर सख्त प्रशासनिक रुख दिखाया, वहीं बच्चों को दुलारने और महिलाओं की समस्याएं गंभीरता से सुनने में पूरी संवेदनशीलता दिखाई। समस्या लेकर आई महिलाओं के साथ आए बच्चों को उन्होंने चाकलेट के साथ खूब पढ़ने का आशीर्वाद दिया। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने गुरु ब्रह्मसलीन महंत अवेद्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। उन्होंने तड़के गोरखनाथ मंदिर में शिवावतार गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मसलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर शीश नवाया। पूजा-अर्चना के बाद मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री गोशाला में पहुंचे और वहां कुछ समय व्यतीत किया।

नई दिल्ली (एजेंसी)। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए देश में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अपने नए लक्ष्य को मंजूरी दी है। जिसमें 2035 तक देश में 400 करोड़ टन कार्बन सिंक का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उत्सर्जन तीव्रता को भी 2035 तक 2005 की जीडीपी की तुलना में 47 प्रतिशत कम करने और 60 प्रतिशत अपनी ऊर्जा मांग को भी



गैर-जीवाश्म ईंधन से पूरा करने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में एनडीसी के नए लक्ष्यों को मंजूरी दी गई है। साथ ही पिछले एनडीसी लक्ष्यों को लेकर हुई प्रगति को भी सराहा

है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में दिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत भारत ने 2031 से 2035 तक के लिए अपने नए लक्ष्य तय किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की ये प्रतिबद्धताएं 2047 तक देश को विकसित बनाने और 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक पहल है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पाण्डुर्णा जिले को जामसांवली मंदिर से दी 362 करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार सच्चा वादा और पक्का काम के ध्येय को साकार करते हुए संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ रही है। उज्जैन में 3 साल पहले बाबा महाकाल का महालोक बना। उसके बाद प्रदेश में प्रमुख तीर्थ स्थलों को धाम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। आज चैत्र नवरात्रि में पाण्डुर्णा के जामसांवली मंदिर में श्री हनुमान लोक सहित 362 करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन अद्भुत अवसर है। उन्होंने जामसांवली श्री हनुमान लोक के दूसरे चरण के विकास कार्यों के लिए घोषणा की तथा बताया कि यहां श्रद्धालुओं के लिए 10 बिस्तर का छोटा अस्पताल भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्रीराम नवमी के अवसर पर शुकवार को भोपाल से राजा रामचंद्र धाम ओरछा के लिए पीएमश्री हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ होगा। श्री हनुमान लोक का लोकार्पण प्रदेश में राम राज्य की स्थापना के प्रति सरकार की आस्था को प्रकट करता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव पाण्डुर्णा में स्थित जामसांवली मंदिर में श्री हनुमान लोक के प्रथम चरण के लोकार्पण अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।



मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 111 करोड़ 63 लाख रूपए की लागत के 31 विकास कार्यों का लोकार्पण और 251 करोड़ 18 लाख रूपए की लागत के 33 विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व-सहायता समूह की बहनों को ऋषा स्वीकृति पत्र और किसानों को पट्टों का वितरण किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को पाण्डुर्णा जिले की पहचान संतरे की उलिया भेंट की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र

के समय जब भी हनुमान जी को याद किया, उन्होंने पल भर में समस्या का समाधान कर दिया। जय बजरंगबली से हमें सौख मिलती है कि जीवन में कभी भी विनम्रता को नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही मन-बुद्धि के साथ अपने शरीर के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नव गठित पाण्डुर्णा जिले में लंबे समय से कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की आवश्यकता थी। इसकी पूर्ति करते हुए अब पाण्डुर्णा को जिला पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालय के भवन की सौगात भी मिल रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पाण्डुर्णा जिले के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जामसांवली श्री हनुमान लोक के दूसरे चरण के विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। पाण्डुर्णा में 10 एकड़ भूमि पर इंडोर और आउट डोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। जिले में नगरपालिकाओं के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी। पाण्डुर्णा जिले में महिला पुलिस थाना बनाया जाएगा। सौसर में कृषि विकास केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कन्हान नदी पर 30 करोड़ 50 लाख रूपए की लागत से बने पुल, मोहागांव से नानदवाडी तक 22 करोड़ 68 लाख रूपए की लागत से बनी 24 कि.मी. लंबी सड़क, विभिन्न ग्रामों की नल-जल योजनाओं, नगर पालिका परिषद सौसर के विभिन्न कार्यों, शासकीय महाविद्यालय पाण्डुर्णा में अतिरिक्त कक्ष और 4 ग्राम पंचायतों में अटल सेवा केंद्रों का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया, उनमें 69 करोड़ 49 लाख रूपए की लागत से बने वाला संयुक्त जिला कार्यालय भवन सहित जिला चिकित्सालय और शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के विभिन्न विकास कार्य, 21 करोड़ 48 लाख रूपए की लागत से बने वाला पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा पुलिस विभाग से जुड़े विभिन्न विकास कार्य, 61 करोड़ 38 लाख रूपए की लागत से पाण्डुर्णा में बने वाला रेलवे ओवर ब्रिज प्रमुख हैं।

प्रदूषण फैलाओ और भुगतान करो की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पर्यावरण नियमों के उल्लंघन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट को बताया गया कि परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक ठोस सुस्था उपाय है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि प्रदूषणकारी भुगतान कर के सिद्धांत को प्रदूषण फैलाओ और भुगतान करो में नहीं बदला जाना चाहिए।

चीफ जस्टिस (सीजेआइ) सुर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ वनशक्ति फेसले से जुड़ी पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। यह मामला उन परियोजनाओं को पिछली तारीख से मंजूरी देने से जुड़ा है, जिन्होंने बिना अनिवार्य पर्यावरणीय



अनुमति के परिचालन शुरू कर दिया था। अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर देशों की उदासीनता सुनवाई के दौरान जब एडवोकेट सृष्टि अग्निहोत्री ने रियो घोषणापत्र और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों का हवाला दिया, तो पीठ ने एक कड़वी सच्चाई साझा की। कोर्ट ने टिप्पणी की कि रियो घोषणा और पेरिस सिद्धांतों जैसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के बावजूद, कई देश इनसे

बचने के रास्ते तलाश रहे हैं। पीठ ने विशेष रूप से अमेरिका और चीन का जिक्र करते हुए कहा कि ये देश इन घोषणाओं के प्रति उदासीन हैं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत कम कदम उठाते हैं। अग्निहोत्री ने तर्क दिया कि एक बार परियोजना शुरू हो जाने के बाद, पर्यावरणीय विकल्पों का विश्लेषण केवल कागजी कवायद बनकर रह जाता है क्योंकि नुकसान पहले ही हो चुका होता है। उन्होंने चेलावनी दी कि यदि भूकंपीय क्षेत्र या भू-क्षरण वाले क्षेत्रों में गलत तरीके से परियोजनाएं बनाई गईं, तो अंततः सार्वजनिक धन की ही बर्बादी होगी। सरकार और कोर्ट के बीच कानूनी बहस केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सालिसिटर जनरल

ऐश्वर्या भाटी ने कार्यालय ज्ञापन का बचाव किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी परियोजना को थोक में नियमित नहीं कर रही है। भाटी ने कहा कि उल्लंघन करने वाली इकाइयों को पहले बंद किया जाता है, फिर उन पर भारी जुर्माना लगाया जाता है और उन्हें सुधार योजना सौंपनी होती है। उन्होंने इसे पर्यावरण न्यायशास्त्र का विस्तार बताया।

हालांकि, जस्टिस जोयमाल्या बागची ने प्रवर्तन पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य और केंद्र सरकारें कानून के शासन की संरक्षक हैं, वे बिना मंजूरी के चल रही परियोजनाओं से अनभिज्ञ होने का दावा नहीं कर सकतीं। उन्होंने चिंता जताई कि वर्तमान व्यवस्था कहीं पर्यावरण नियमों के पालन की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त न कर दे। बहरहाल, मामले की सुनवाई अगले सप्ताह भी जारी रहेगी।

फतेहगढ़ साहिब में एनकाउंटर- बंबीहा गैंग का शूटर घायल, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शूटआउट में था शामिल



नई दिल्ली (एजेंसी)। पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) और चंडीगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने वीरवार दोपहर फतेहगढ़ साहिब जिले के अमलोह कस्बे के पास नूरपुर गांव में बंबीहा गैंग के एक शूटर को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। गोली लगने से घायल हुआ आरोपी जसप्रीत सिंह उर्फ जस्स अस्पताल में उपचारार्थ है। पुलिस के मुताबिक, जस्स हाल ही में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शूटआउट में शामिल था। पुलिस के अनुसार, एजीटीएफ और चंडीगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध शूटर कार में अमलोह की ओर जा रहा है। इस सूचना पर एजीटीएफ और चंडीगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने इस्पेक्टर विक्रम और सब-इस्पेक्टर अमन की अगुवाई में पीछा शुरू किया। नूरपुर गांव के पास पहुंचते ही संदिग्ध ने कार रोक दी और पुलिस पर गोलियां चला दीं। डीएसपी राजन परमिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। दोनों ओर से करीब 10 राउंड गोलियां चलीं।

पश्चिम एशिया संकट पर सर्वदलीय बैठक- सरकार का दावा, भारत का ऊर्जा भविष्य सुरक्षित; विपक्ष से मिला सहयोग



नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में वक्तव्य दिए जाने के बाद सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष की चिंताओं-जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का जवाब दिया गया है।

इन परिस्थितियों से निपटने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देते हुए आश्वासन दिया गया है कि भारत का ऊर्जा भविष्य सुरक्षित है। सरकार ने दावा किया कि विपक्ष ने सहयोग-समर्थन का वादा करते हुए एकजुटता का संदेश दिया है। वहीं, कांग्रेस ने बैठक पर असंतोष जताते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा ही विपक्ष की पहली मांग है। संसद भवन परिसर में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। करीब पौने दो घंटे चली बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री किरन रिजिजू ने बताया कि बैठक में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

संसद में आम लोगों की रकम लेकर भागी चिट फंड कंपनियों से पैसा वापस दिलाने की उठी मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में आम लोगों की खून-पसीने की कमाई लेकर भाग जाने वाली चिट फंड कंपनियों के हेर-फेर के खेल का मामला जोर से उठाया गया। इनसोल्वेंसी और बैंकरप्सी कानून में संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान चंडीली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने देशभर के लाखों किसानों, मजदूरों एवं छोटे निवेशकों की पीड़ा को उठाते हुए कहा कि यह कानून बड़े उद्योग घरानों को राहत देने का माध्यम बनता जा रहा है मगर आम जनता की गाढ़ी कमाई आज भी विभिन्न चिटफंड एवं निवेश कंपनियों में फंसी हुई है। वीरेंद्र सिंह ने उठाया मुद्दा- उत्तरप्रदेश समेत



देश भर में चिट फंड कंपनियों के हेर-फेर के खेल का उल्लेख करते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी कंपनियों ने अपने एजेंटों के माध्यम से गांव-गांव जाकर छोटे किसानों, मजदूरों और गरीब परिवारों को ऊंची ब्याज दर एवं दोगुना मुनाफा देने का लालच देकर हजारों

करोड़ रुपये का निवेश कराया मगर आज वे कंपनियां पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी हैं। ऐसे में निवेशकों की जमा पूंजी वापस दिलाने में केंद्र सरकार को ठोस पहल करनी चाहिए जो अभी नजर नहीं आ रही। कंपनियों की संपत्तियां बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाने की सरकार की पहल के संदर्भ में वीरेंद्र सिंह ने कहा कि संपत्तियां बेचकर धन तो एकत्र किया गया मगर पैसा सीधे पीड़ितों के खातों में पहुंचाने के बजाय सहाकारिता विभाग के बैंकों में जमा कर दिया गया। अब निवेशकों को तरह-तरह के कागजी प्रक्रियाओं में उलझाकर उनका पैसा रोक जा रहा है और उस पर उचित ब्याज भी नहीं दिया जा रहा है।

देश के तय किए गए एनडीसी लक्ष्य: 2035 तक चार सौ करोड़ टन का कार्बन सिंक का करेगा निर्माण

नई दिल्ली (एजेंसी)। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए देश में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अपने नए लक्ष्य को मंजूरी दी है। जिसमें 2035 तक देश में 400 करोड़ टन कार्बन सिंक का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उत्सर्जन तीव्रता को भी 2035 तक 2005 की जीडीपी की तुलना में 47 प्रतिशत कम करने और 60 प्रतिशत अपनी ऊर्जा मांग को भी

गैर-जीवाश्म ईंधन से पूरा करने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में एनडीसी के नए लक्ष्यों को मंजूरी दी गई है। साथ ही पिछले एनडीसी लक्ष्यों को लेकर हुई प्रगति को भी सराहा

उज्जैन की खुशहाली के लिए चौबीस खंभा देवी को चढ़ा मदिरा का भोग, नगर पूजा यात्रा निकली

महाअष्टमी पर निरंजनी अखाड़े ने परंपरा निभाई, 27 किमी की नगर पूजा यात्रा में 40 से अधिक मंदिरों में हुआ पूजन



दैनिक दिव्य संवाद उज्जैन। चैत्र शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी पर गुरुवार को धार्मिक नगरी उज्जैन में प्राचीन परंपरा के अनुसार चौबीस खंभा स्थित माता महामाया और महालया का पूजन-अर्चन कर उन्हें मदिरा का भोग अर्पित किया गया। निरंजनी अखाड़े की ओर से अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रवीन्द्रपुरी महाराज ने विधिविधान से पूजा कर

महाआरती संपन्न कराई। महा अष्टमी पर गुरदरी स्थित 24 खंभा माता मंदिर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज द्वारा देवी को मदिरा तथा बड़वाकल का भोग लगाया गया और सुहाग सामग्री अर्पित की गई। पूजन के पश्चात नगर पूजा यात्रा प्रारंभ हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए 40 से अधिक देवी और भैरव मंदिरों में पहुंची। लगभग 27 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का समापन अकंपात मार्ग स्थित हांडीफोड भैरव मंदिर पर हुआ। पूरे मार्ग में पारंपरिक रूप से मदिरा की धार बहाई गई, जो इस विशेष धार्मिक आयोजन की प्रमुख पहचान रही। नगर पूजा यात्रा में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरी, स्वामी प्रेमानंद पुरी, स्वामी सुमानंद गिरी, स्वामी भागवतानंद गिरी, स्वामी रामकृष्णानंद महाराज सहित विभिन्न अखाड़ों के संत-महंत, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी महाराज और साधु-संतों द्वारा मदिरा से भरी मटकी लेकर यात्रा का नेतृत्व किया गया। बड़वाजों, ढोल-नगाड़ों और तोपचियों की

मौजूदगी से पूरे आयोजन का धार्मिक और पारंपरिक स्वरूप और भी भव्य हो उठा। उल्लेखनीय है कि चैत्र मास की अष्टमी पर उज्जैन में नगर पूजा की यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, जिसका निर्वहन निरंजनी अखाड़े द्वारा किया जाता है। आयोजन के अंतर्गत देवी को सुहाग सामग्री और बड़वाकल का भोग भी अर्पित किया गया।

निरंजनी अखाड़े में आज होगा कन्या पूजन और भंडारा...

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता डॉ गोविंद सोलंकी और समन्वयक डॉ राहुल कटारिया ने बताया कि आयोजन के अगले दिन आज शुक्रवार को बडनगर रोड स्थित श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी में कन्या पूजन एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और विभिन्न अखाड़ों के साधु संत शामिल होंगे।

आज रामनवमी पर निकलेगा वीरभद्र ध्वज चल समारोह



उज्जैन। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आज रामनवमी के पावन भव पर ऐतिहासिक वीरभद्र ध्वज चल समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वीरभद्र ध्वज चल समारोह समिति के तत्वावधान में यह समारोह महाकाल इंटरनेशनल चौराहे से शाम 7-00 बजे आरंभ होगा।

झाकियां और बैंड बढाएंगे समारोह की भव्यता-यह ध्वज चल समारोह महाकाल इंटरनेशनल चौराहे से शुरू होकर शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए रात्रि 9-30 बजे गोपाल मंदिर पहुंचेगा। इस बार ध्वज चल समारोह में मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए बैंड और आकर्षक झाकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी, जो समारोह की भव्यता को और बढ़ाएंगी।

आयोजन को लेकर महाकाल इंटरनेशनल चौराहा मित्र मंडल ने शहर की समस्त सनातनी धर्मप्रेमी जनता से अनुरोध किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस ऐतिहासिक वीरभद्र ध्वज चल समारोह में पधारकर धर्म लाभ अर्जित करें और इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाएं।

आज होगा रामघाट पर श्री राम स्तुति कार्यक्रम कन्या पूजन के बाद राम प्रसादी (भंडारा) होगा

उज्जैन। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अयोध्या में राजा दशरथ की पत्नी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ था, जिसे रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी यज्ञ के प्रसाद स्वरूप, माता कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को, और सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया।

चरक अस्पताल में सनसनी: इमरजेंसी गेट के पास सीवरेज चैंबर से सड़ी-गली लाश बरामद

तेज बदबू से खुला राज, कचरे के बीच मिली अज्ञात शव; कई दिनों पुराना होने की आशंका, पुलिस जांच में जुटी



दैनिक दिव्य संवाद उज्जैन। जिला अस्पताल के चरक भवन में गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब इमरजेंसी गेट के ठीक पास बने सीवरेज चैंबर से एक सड़ी-गली लाश बरामद हुई। बदबू इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद लोग परेशान हो उठे और आखिरकार इसी दुर्गंध ने इस खौफनाक राज से पर्दा उठाया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10 बजे अस्पताल स्टाफ को इमरजेंसी गेट के पास से अस्मायुक्त बदबू आने का अहसास हुआ। पहले तो इसे सामान्य गंधवी समझकर नजरअंदाज किया गया, लेकिन जब बदबू बढ़ती गई तो कर्मचारियों ने सीवरेज लाइन के लिए बनाए गए कैबिन की जांच की। जैसे ही अंदर झांका गया, कचरे के ढेर के बीच एक लाश पड़ी मिली, जो बुरी तरह सड़ चुकी थी। मृतक ने टी-शर्ट पहन रखी थी, लेकिन शव की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसकी पहचान कर पाना फिलहाल संभव नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है कि लाश कई दिनों से वहीं पड़ी थी और धीरे-धीरे सड़ने के कारण बदबू फैलने लगी। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मृतक कौन था और वह इस सीवरेज चैंबर तक कैसे पहुंचा। अस्पताल परिसर में इस तरह लाश मिलने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इमरजेंसी गेट जैसे संवेदनशील इलाके के पास इतने दिनों तक किसी को इस घटना की भनक तक कैसे नहीं लगी। फिलहाल पुलिस मामले का काम कर मामले की जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की तैयारी की जा रही है, ताकि इस रहस्यमयी मौत से पर्दा उठाया जा सके।

दैनिक दिव्य संवाद उज्जैन। शहर की सड़कों पर अब लापरवाही भारी पड़ेगी। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यातायात व्यवस्था को लेकर कड़े फैसले लिए गए। बैठक में साफ संकेत दिया गया कि अब नियम तोड़ने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी और खतरनाक स्थानों को सुरक्षित बनाने के लिए तेजी से काम होगा। सबसे ज्यादा फोकस शहर के ब्लैक स्पॉट्स यानी दुर्घटना संभावित जगहों पर रहा। कलेक्टर ने एमपीआरडीसी, लोक निर्माण विभाग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और नगर निगम को निर्देश दिए कि ऐसे स्थानों को तुरंत चिह्नित कर वहां संकेतक बोर्ड, रंबल स्ट्रिप और पार्किंग व्यवस्था विकसित की जाए। ताकि हादसों पर लगाम लग सके। यातायात को सुगम बनाने के लिए चारधाम और नीलकंठ द्वार मार्ग पर ई-रिक्शा के ड्रॉप प्वाइंट तय करने के निर्देश दिए गए। इससे अव्यवस्थित

उज्जैन में सड़क सुरक्षा पर सख्ती: ई-रिक्शा ड्रॉप प्वाइंट तय होंगे, खतरनाक ब्लैक स्पॉट्स पर लगे संकेतक

स्कूल बसों की जांच से लेकर वाहन चालकों पर नजर, नियम तोड़े तो तुरंत चालान-कलेक्टर और एसपी ने दिए सख्त निर्देश

दैनिक दिव्य संवाद उज्जैन। शहर की सड़कों पर अब लापरवाही भारी पड़ेगी। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यातायात व्यवस्था को लेकर कड़े फैसले लिए गए। बैठक में साफ संकेत दिया गया कि अब नियम तोड़ने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी और खतरनाक स्थानों को सुरक्षित बनाने के लिए तेजी से काम होगा।



पाकिंग और जाम की समस्या को कम करने की तैयारी है। नगर निगम, यूडीए और पुलिस को मिलकर एक ठोस ट्रैफिक प्लान बनाने को कहा गया है। ई-रिक्शा और दोपहिया वाहनों की सघन जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। हेल्मेट नहीं पहनने, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने और सीट बेल्ट की अनदेखी करने वालों पर सख्त चालानी कार्रवाई होगी। अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया कि नियमों का पालन हर हाल में कराया जाए। स्कूल और कॉलेज बसों की सुरक्षा पर भी बैठक में गंभीरता दिखाई गई। सभी बसों की फिटनेस,

सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा मानकों की नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं, ताकि छात्रों की सुरक्षा में कोई चूक न हो। इसके अलावा मंडियों में आने वाली ट्रैक्टर-ट्रालियों पर रिफ्लेक्टर लगाने की कार्रवाई लगातार जारी रखने को कहा गया है, जिससे रात के समय हादसों की संभावना कम हो सके।

बैठक की खास बातें...

- ब्लैक स्पॉट्स पर फोकस- खतरनाक स्थान चिह्नित कर तुरंत सुधार कार्य
- ई-रिक्शा व्यवस्था- चारधाम-नीलकंठ मार्ग पर ड्रॉप प्वाइंट तय होंगे
- स्कूटी चालकों पर सख्ती- हेल्मेट नहीं तो सिला चालान
- स्कूल बसों की जांच- फिटनेस और सीसीटीवी अनिवार्य
- ट्रैक्टर-ट्राली पर रिफ्लेक्टर- हादसे रोकने के लिए सतत अभियान
- मोबाइल पर बात की तो कार्रवाई- ट्रैफिक नियमों की अनदेखी नहीं चलेगी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सप्लीक श्री अंगारेश्वर महादेव का पूजन, दर्शन कर अभिषेक किया



उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में आज प्रातः कालीन समय में उज्जैन स्थित श्री अंगारेश्वर महादेव का पूजन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परिवार संग आज गुरुवार प्रातः श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और पंचामृत से पूजन अभिषेक किया और प्रदेश की जनता की सुख समृद्धि की कामना की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नव निर्मित हो रहे घाटों का निरीक्षण किया



उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में आज गुरुवार को शिप्रा नदी पर सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए बन रहे घाटों का अंगारेश्वर और सिद्धवट क्षेत्र में निरीक्षण किया।

इंजीनियरिंग कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन, निर्माण क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को मिलेगी रपतार

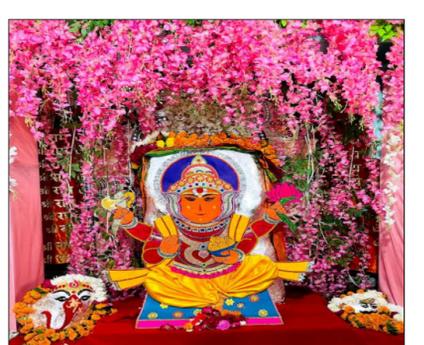


उज्जैन। निर्माण क्षेत्र में नवाचार, कौशल विकास और सतत तकनीकों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अल्ट्राटेक सीमेंट ने उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के सहयोग से कॉलेज परिसर में अत्याधुनिक %सेंटर ऑफ एक्सीलेंस% की स्थापना की है। यह केंद्र आधुनिक निर्माण चुनौतियों के समग्र समाधान और इंजीनियरिंग समुदाय के साथ सहयोग मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदर्शित किए गए आधुनिक निर्माण समाधान इस नवनिर्मित केंद्र में अल्ट्राटेक के विविध निर्माण समाधानों का प्रदर्शन किया गया है। इनमें रेडीप्लास्ट, टाइल चिपकाने वाले पदार्थ, वॉटरप्रूफिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल ग्राउंट्स और वैल्यू-एडेड कंक्रीट उत्पाद शामिल हैं। शोध और कौशल विकास का बनेगा प्रमुख केंद्र उत्पाद प्रदर्शनी के साथ ही यह केंद्र अनुसंधान, विकास और ज्ञान विनिमय के मंच के रूप में भी कार्य करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के लिए सतत निर्माण सामग्रियों पर केंद्रित समाधान विकसित करना है। इसके तहत एप्लीकेटर्स, कॉन्ट्रैक्टरों और बिल्डर्स के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। साथ ही, भावी इंजीनियरों,

आर्किटेक्ट्स और टेक्नोक्रेट्स के बीच आधुनिक बिल्डिंग सॉल्यूशंस को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। छात्रों और पेशेवरों को मिलेंगे ये लाभ इस केंद्र में निर्माण प्रौद्योगिकी की नवीनतम प्रगति पर तकनीकी सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छात्रों को वैश्विक औद्योगिक रुझानों से जोड़ने के लिए औद्योगिक भ्रमण, विशेषज्ञ व्याख्यान और उद्योग पेशेवरों के साथ संवाद की सुविधा मिलेगी। साथ ही सीमेंट और निर्माण सामग्रियों के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाएं शुरू कर सहयोगात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज की यह पहल उद्योग और शैक्षणिक जगत के

सहयोग को उल्लेखनीय रूप से मजबूत करेगी। इससे पेशेवरों, सरकारी निकायों और छात्रों में समाधान-उन्मुख सोच विकसित करने के लिए एक सशक्त मंच मिलेगा। उद्घाटन समारोह में इनकी रही उपस्थिति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता एच. आर. राठी, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉ. उमेश पेंढारकर, सिविल इंजीनियरिंग के विभागाध्यक्ष डॉ. बी. के. सिंह और अल्ट्राटेक के क्षेत्रीय प्रमुख सेल्स एवं मार्केटिंग अभि. निलेश अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शहर के प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के प्रमुख चैनल पार्टनर्स ने भी हिस्सा लिया।

श्री मायापति हनुमान मंदिर में 28 मार्च से मनेगा 6 दिवसीय जन्मोत्सव, निकलेगी कलश यात्रा



उज्जैन। आगर रोड, सामाजिक न्याय परिसर (चरक भवन के सामने) स्थित श्री मायापति हनुमान मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। श्री मायापति हनुमान मंदिर परिवार द्वारा 28 मार्च से 2 अप्रैल तक छह दिवसीय विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सुंदरकांड पाठ और तुलादान महोत्सव-कार्यक्रम की शुरुआत 28 मार्च से होगी। 28 से 30 मार्च तक प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक श्री गिरीश शर्मा के मुखारविंद श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पाठ एवं व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ 29 और 30 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मंदिर परिसर में तुलादान महोत्सव संपन्न होगा।

निकलेगी भव्य कलश यात्रा, होगा गंगा माता पूजन- 31 मार्च को सांस्कृतिक श्री गंगा माता पूजन का विशेष आयोजन रखा गया है। इस अवसर पर सुबह क्षीरसागर मानस भवन से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों बहादुरगंज, मालीपुरा, देवास गेट और चामुंडा माता चौराहा से होते हुए मंदिर परिसर पहुंचेगी। यात्रा के समापन के पश्चात सामूहिक रूप से श्री गंगा माता पूजन किया जाएगा। अखंड रामायण पाठ और विशाल भंडारा- 1 अप्रैल को सुबह 9 बजे से श्री रामचरितमानस अखंड रामायण पाठ शुरू होगा। इसी दिन रात्रि में बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के मुख्य पर्व पर सुबह 9 बजे हवन होगा। 3 बजे महाआरती और भजन संख्या का आयोजन किया जाएगा, जिसके पश्चात विशाल भंडारे में श्रद्धालु प्रसादी ग्रहण करेंगे।

प्रेस क्लब को मिली भवन की सौगात



उज्जैन। प्रेस क्लब के स्थापना दिवस एवं माननीय मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव ने शहर के मीडिया कर्मियों को प्रेस भवन की सौगात दी। आपने कहा आने वाले समय में सिंहस्थ आयोजित होगा, और करोड़ों लोगों का आगमन शहर में होगा इस आयोजन के लिए शहर वासी भी तैयार रहें साथ ही इस आयोजन में मीडिया कर्मियों की भूमिका भी विशेष हो जाती है। सिंहस्थ के दौरान पूरे देश का मीडिया उज्जैन

व्यवस्थाएं होंगी। आपने कहा सिंहस्थ 2028 को देखते हुए शहर में कई निर्माण कार्य चल रहे हैं जो इस शहर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। आयोजन की अध्यक्षता करते हुए प्रेस क्लब के अध्यक्ष नंदलाल यादव ने कहा कि प्रेस सिंहस्थ के लिए पूरी तरह तैयार है और बाहर से आने वाले पत्रकारों के स्वागत में भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। आयोजन में भगवान श्री राम का पूजन भी धूमधाम से किया जाकर क्लब का स्थापना दिवस मनाया गया। आयोजन में माननीय के सम्मान में केक सेरेमनी भी की गई। स्वागत कार्यकारी अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा ने किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिप्रा नदी पर निर्माणाधीन नवीन घाटों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए



दैनिक दिव्य संवाद उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार सुबह 8 बजे श्री अंगारेश्वर महादेव की पूजा करने पहुंचे। पूजा के उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री अंगारेश्वर और श्री सिद्धवट

के बीच शिप्रा नदी पर बन रहे नवीन घाटों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त श्री आशीष सिंह ने बताया कि उक्त घाट सिद्धवट महादेव 2028 में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए बनाए जा रहे हैं और घाट

पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी, इस संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए कि नवीनघाटों के 200 मीटर क्षेत्र में श्रद्धालुओं को

कपड़े बदलने, टॉयलेट सुविधाजनक स्थान पर बनाया जाए, इसके लिए मुख्य - मुख्य घाटों पर 200 मीटर की दूरी पर सुविधा घर बनाए जाएं।

आने जाने के लिए 500 मीटर दूरी पर सीढ़ियां और अन्य पहुंच मार्ग की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो, जिससे मुख्य घाटों पर श्रद्धालुओं को स्नान करने में सुविधा भी होगी। श्री सिद्धवट और श्री अंगारेश्वर मंदिर के मध्य बन रहे पुल का भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा अवलोकन किया गया।

कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने बताया कि इस पुल के बनने के बाद दोनों प्रमुख मंदिर स्थानों को जोड़ने के लिए सुविधा भी हो जाएगी और श्रद्धालुओं को एक नया वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध होगा। इसके साथ ही घाटों पर स्नान करने के लिए 5 मीटर का बड़ा घाट भी बनाया गया है जो आने-जाने एवं श्रद्धालुओं के बैठने की सुविधा भी प्रदान करेगा।

इसी के साथ घाटों पर श्रद्धालुओं की बैठने के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करने के निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा अधिकारियों को दिए गए हैं।

महाराष्ट्र समाज के राम मंदिर में मना राम जन्मोत्सव



उज्जैन। राम नवमी के पावन पर्व पर महाराष्ट्र समाज के राम मंदिर में राम जन्मोत्सव पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अर्चना आपटे तिवारी और उनके समूह द्वारा भगवान श्रीराम को समर्पित सुंदर भजनो की संगीतमय प्रस्तुति दी गई।

आयोजन में महाराष्ट्र समाज उज्जैन के अध्यक्ष पंकज चांदोरकर, उपाध्यक्ष सदाशिव नायगावकर, कोषाध्यक्ष रवींद्र मुळे, सहसचिव मिलिंद पन्हाळकर, कार्यकारिणी सदस्य निलेश नेवाळकर, अभय आरोंदेकर, नरेंद्र पांडे, उदय सोले, निलेश फडणीस, लाभेश जोशी और चंद्रकांत फटले उपस्थित थे।

साथ ही श्री एवं श्रीमती दिनेश ठाकरे, श्री एवं श्रीमती धनंजय पटवर्धन, श्री एवं श्रीमती राजेश सोहनी, श्रीमती जोशी सहित समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

मंदिर परिसर की आकर्षक सजावट पुजारी केकरे और पैठणी द्वारा की गई। कार्यक्रम की यह जानकारी आयोजन के संयोजक व समाज कार्यकारिणी के सदस्य प्रदीप जोग ने दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 10 महाविद्या की प्रतिष्ठा अनुष्ठान में दूसरी बार शामिल



उज्जैन। मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन के भैरवगढ़ रोड पर स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में चल रहे 10 महाविद्या की मूर्ति प्रतिष्ठा अनुष्ठान में दूसरी बार शामिल हुए।

भर्तृहरि गुफा के गौदीपति योगी पार महंत श्री रामनाथ जी महाराज के सानिध्य में यहां प्रतिष्ठा अनुष्ठान चैत्र नवरात्रि में किया जा रहा है। मंदिर परिसर में मां बगलामुखी के अलावा 10 महाविद्याओं में शामिल देवियों के साथ विक्राल भैरव की मूर्ति प्रतिष्ठा की गई है। आज रामनवमी पर्व पर श्री रामलला और हनुमान जी की प्रतिष्ठा होगी। इसके साथ ही यह नौ दिनी अनुष्ठान पूर्ण होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव अनुष्ठान के पहले दिन भी शामिल हुए थे तथा दूसरे दिन सप्तमी की रात हवन में शामिल हुए व जनकल्याण, विश्व कल्याण हेतु आहुतियां डाली।

लायंस रीजन कॉन्फ्रेंस सहर्ष 29 मार्च को

विशेष सेवा और प्रशासनिक कार्यों के लिए रीजन के उत्कृष्ट क्लब और व्यक्ति होंगे सम्मानित

उज्जैन। लायंस क्लब इंटरनेशनल के रीजन-01 के तत्वावधान में रीजन कॉन्फ्रेंस +सहर्ष- 2026 का गरिमामय आयोजन आगामी रविवार, 29 मार्च 2026 को कोटी रोड स्थित स्मार्ट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के %स्वर्ण जयंती हॉल% में होने जा रहा है। रीजन चेयरपर्सन लयन डॉ. सत्येंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता पीएमजेएफ लयन टी.बी. श्रवण कुमार, एल.सी.आई.एफ. एरिया लीडर (मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 3233 एवं 3234) रहेंगे। सम्मेलन की मेजबानी लायंस क्लब उज्जैन डायमंड कर रहा है।

मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख उद्देश्य रीजन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्लबों और उनके सदस्यों



के उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। सम्मेलन में उन क्लबों अथवा विशिष्ट व्यक्तियों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने चालू सत्र के दौरान सेवा प्रकल्पों, प्रशासनिक क्षेत्र या किसी अन्य विशेष कार्य में असाधारण प्रदर्शन कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के

रीजन कॉन्फ्रेंस के लिए चेयरपर्सन एमजेएफ लयन संजय मिल्ल, सचिव एमजेएफ लयन जे.पी. पंचारिया और कोषाध्यक्ष लयन अमित शुक्ला को टीम सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

आयोजन के लिए विभिन्न समितियां गठित कॉन्फ्रेंस को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। इनमें आशीर्वाद दाता, सलाहकार समिति, स्वागत समिति, रजिस्ट्रेशन समिति, स्वागत एवं तिलक समिति, किट वितरण समिति, आई.टी., कॉन्फ्रेंस व्यवस्था समिति, मंच व्यवस्था, पुरस्कार वितरण समिति, प्रोटोकॉल ऑफिसर, चिकित्सा सेवा समिति, बैनर प्रस्तुतीकरण, भोजन समिति, फोटो एल्बम, स्क्रैप बुक व पिन कलेक्शन, लक्ष्मी ड्रॉ और मीडिया प्रभारी शामिल हैं।

चैत्र नवरात्रि पर श्री रविदास

सेवक संघ का चल समारोह आज

उज्जैन। श्री रविदास सेवक संघ, जिला उज्जैन के तत्वावधान में आयोजित चैत्र नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत समाज द्वारा श्रद्धा और भक्ति के साथ जवारे (घट) स्थापना की गई। नौ दिनों तक समाज की महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठजनों ने विधि-विधान से माता जी की सेवा-अर्चना कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। संस्था के अध्यक्ष सदीप सूर्यवंशी ने बताया कि महोत्सव के समापन अवसर पर शुक्रवार, 27 फरवरी 2026 को भव्य चल समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह चल समारोह शाम 5:00 बजे राजू नगर स्थित समाज की धर्मशाला से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में आकर्षक चुनरी यात्रा भी शामिल रहेगी।

जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक महिलाएं एवं समाजजन सहभागिता करेंगी। चल समारोह राजू नगर धर्मशाला से प्रारंभ होकर आगर रोड, गाड़ी अड्डा एवं फाजिलपुर मार्ग से होते हुए नगरकोट महारानी मंदिर पहुंचेगा, जहां माता रानी के दर्शन एवं आशीर्वाद लिया जाएगा। यह आयोजन समाज में एकता, श्रद्धा और सांस्कृतिक परंपराओं को सशक्त करने का संदेश देता है। उन्होंने सभी समाजजनों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है।

रामनवमी पर हुआ मध्य प्रदेश गुजराती सेन समाज ट्रस्ट का 41वां सामूहिक विवाह सम्मलेन

उज्जैन। मोहनपुरा, बड़नगर रोड स्थित चार भुजा गार्डन में मध्य प्रदेश गुजराती सेन समाज ट्रस्ट के तत्वावधान में रामनवमी (26 मार्च) के पावन पर्व पर सर्व सेन समाज का 41वां निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मलेन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस समारोह में 29 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे।

प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान, ट्रस्ट अध्यक्ष संतोष वर्मा, कैलाश चौहान, समिति अध्यक्ष गुड्डू पहलवान ने बताया कि कार्यक्रम को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वचुंअली संबोधित किया। उन्होंने नवदंपतियों के उज्वल भविष्य की कामना करते हुए सभी 29 जोड़ों को 11-11 हजार रुपये और मध्य प्रदेश गुजराती सेन समाज ट्रस्ट विवाह समिति को एक लाख रुपये देने की घोषणा की। समारोह में समाज की ओर से एक अनुकरणीय पहल करते हुए सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया, जिसके तहत उपहार सामग्री के साथ प्रत्येक दूल्हे को सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेलमेट भेंट किया गया।

देश भर से पधारे अतिथि और समाजजन समारोह में देश भर से हजारों समाजजन और कई गणमान्य अतिथि



उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों में भाजपा नेता सुंदर यादव, पार्षद सुशील श्रीवास, पिछड़ा मोर्चा नगर अध्यक्ष प्रकाश जायसवाल, महामंत्री पुष्कर यादव, उपाध्यक्ष संतोष पंवार, अमित श्रीवास्तव, जितेंद्र पटेल, इंदौर के उद्योगपति व पूर्व जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा, शिव नारायण राहलोट, संजय भाती, शिवनारायण झाला, महेंद्र सेन, महावीर सेन और नीलेश वर्मा शामिल रहे। इनकी रही प्रमुख उपस्थिति-

आयोजन में ट्रस्ट संरक्षक अशोक राठौर, प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान, ट्रस्ट अध्यक्ष संतोष वर्मा, कैलाश चौहान, समिति अध्यक्ष गुड्डू पहलवान, संभागीय अध्यक्ष परमानन्द सेन, ट्रस्ट उपाध्यक्ष सुरेश सोलंकी, ट्रस्ट सदस्य कैलाश चौहान, मंदिर व्यवस्थापक देवेन्द्र देवड़ा, समिति व्यवस्थापक बाबूलाल वर्मा सिलोदा रावल, पुरुषोत्तम राठौर, नगर अध्यक्ष ओम वर्मा लोहरी, नगर युवा अध्यक्ष अर्जुन वर्मा, उज्जैन दक्षिण

अध्यक्ष सचिन वर्मा, मनोहर परमार, वीरेंद्र परमार, ट्रस्ट कोषाध्यक्ष डॉ. गौरी शंकर वर्मा, समिति कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक सेन, समिति कार्यवाहक अध्यक्ष जगदीश देवड़ा, मदनलाल सोलंकी गिरवार, ट्रस्ट सचिव राधेश्याम वर्मा (दूध संघ), मनोहर लाल सेन अचलखेड़ी और भारतलाल परमार चिखली मौजूद रहे।

साथ ही प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष नवीन वर्मा, ट्रस्ट सदस्य प्रवीण भाटी, युवा प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोलंकी, महिला प्रदेश अध्यक्ष स्मिता सोलंकी, नगर अध्यक्ष निशा वर्मा, आर्यन राठौर, ओमप्रकाश भाटी (बड़नगर), जगदीश वर्मा सिलोदा, संरक्षक ट्रस्टीगण देवनारायण सोलंकी, मोहनलाल वर्मा, कैलाश वर्मा, सुरेश वर्मा, शंकरलाल परमार, ट्रस्ट महासचिव मुलचंद वर्मा, ट्रस्ट सदस्य सुभाष तंवर, ट्रस्ट प्रचार मंत्री शिवनारायण सेन, सुरेश सोलंकी, विशाल चौहान, दिनेश राठौर, बाबूलाल वर्मा, परमानंद वर्मा, संतोष भाटी, राहुल वर्मा, संदीप वर्मा सुरासा, गौरव सेन, रविंद्र वर्मा भैसोदा, पंकज वर्मा, अमृत वर्मा, धर्मेन्द्र सेन उन्हेल, मुकेश भाटी (बड़नगर), अशोक भाटी, ईश्वर भाटी,

प्रह्लाद भाटी, अनिल वर्मा, कुलदीप वर्मा, अजित सेन, महेश परमार, विशाल सरीफ, जितेंद्र परमार कचनारिया, आशीष परमार, सुनील वर्मा बालाजी, भगवानसिंह वर्मा, विजय वर्मा, सुभाष वर्मा, बदीलाल वर्मा (सर), राजाराम सेन भलाई, अजय वर्मा देवली, सुभाष वर्मा (हेड सा.), अशोक वर्मा (लसुडलिया जगमाल), पुष्पेन्द्र परमार, विनोद परमार, गोपाल परमार, राहुल वर्मा (पिपली नाका), महेश वर्मा, ओमप्रकाश वर्मा (सरपंच सा.), गोवर्धनलाल वर्मा लोकोड़, रमेश चन्द्र वर्मा रालामंडल, सत्यनारायण वर्मा, लक्ष्मीनारायण वर्मा, अजय वर्मा देवास, घनश्याम वर्मा हर्सोदैन, आशीष वर्मा (गोलू), ईश्वर सोलंकी, महेश वर्मा (नलवा), पवन वर्मा, विजय सेन, सचिन सेन, राम सेन, श्याम सेन, जितेंद्र सेन (पिपलीनाका), सुरेश वर्मा सोडंग, मोश देवड़ा, आदित्य देवड़ा, विवेक वर्मा, जितेंद्र सेन मोजमखेड़ी, जय सेन, व्यवस्थापक अभिषेक शर्मा, राहुल वर्मा ताजपुर और रतनलाल भाटी सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे।

कार्यक्रम के अंत में ओम वर्मा लाहौरी ने सभी अतिथियों और समाजजनों का आभार व्यक्त किया।

नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में उज्जैन की मोनिका खलोटीया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल



उज्जैन। गोवा में आयोजित 48वीं मास्टर वेटेन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में उज्जैन की मोनिका खलोटीया ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। विक्रमादित्य बैडमिंटन क्लब की प्रतिभावान खिलाड़ी मोनिका ने यह पदक महिला एकल के 35 प्लस आयु वर्ग में हासिल कर न सिर्फ क्लब का, बल्कि पूरे उज्जैन शहर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है।

निरंतर अभ्यास का मिला परिणाम-खिलाड़ी के प्रदर्शन को लेकर कोच योगेश बदेवार ने बताया कि मोनिका नियमित रूप से महानंद स्थित विक्रमादित्य बैडमिंटन क्लब में कड़ा अभ्यास करती हैं। उनकी इसी लगन और निरंतर प्रैक्टिस का परिणाम है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में यह अहम सफलता प्राप्त की है।

विधायक और खेल संघ ने दी बधाई-मोनिका की इस गौरवमयी उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और शहरवासियों में उत्साह है। विक्रमादित्य बैडमिंटन क्लब के संरक्षक व विधायक अनिल जैन कालुहेड़ा, जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव यादव, क्लब अध्यक्ष दिनेश जाटवा, सचिव जितेंद्र मुकाती, राजेश योहान और सुधीर यादव सहित क्लब के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें उज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।

संत शिरोमणि सुंदरदास जी महाराज के 430वें जन्मोत्सव पर निकलेगा ध्वज चल समारोह

उज्जैन। खंडेलवाल वैश्य पंचायत उज्जैन द्वारा चैत्र शुक्ल नवमी के अवसर पर संत शिरोमणि 1008 श्री सुंदरदास जी महाराज के 430वें जन्मोत्सव पर भव्य चल समारोह का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार 27 मार्च को शाम 6 बजे से पंचायत भवन से पारंपरिक निशान ध्वज चल समारोह निकाला जाएगा। इस अवसर पर समाज के विशिष्ट जनों को सम्मान रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाएगा।



एवं संत श्री की आरती की जाएगी। बैड-बाजों और भजनों की प्रस्तुति के बीच बगों में संत श्री की तस्वीर विराजित कर समारोह की शुरुआत होगी। ढोल और निशान ध्वज के साथ यह यात्रा बुधवारिया स्थित भवन से

पूजन के बाद शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी यात्रा

कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार शाम 6 बजे बुधवारिया स्थित खंडेलवाल वैश्य पंचायत भवन पर पारंपरिक निशान पूजन और ध्वजा स्थापना के साथ होगी। इसके पश्चात उक्तूरी जी

प्रारंभ होकर गीता कॉलोनी चौराहा, निकास चौराहा, तेलीवाड़ा चौराहा और गोंदा चौकी होते हुए पुनः पंचायत भवन पहुंचेगी। इस समारोह में समाज की महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल होंगे। चल समारोह के पंचायत भवन वापस लौटने पर सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा।

29वें पुरश्चरण में 29 लाख मंत्रों से की देवी की आराधना देश और उज्जैन की सुख-समृद्धि के लिए हुआ बगलामुखी अनुष्ठान



उज्जैन। उज्जैन और देश की आर्थिक व सामाजिक सुख-समृद्धि की कामना के साथ सप्तमी तिथि पर वृहद बगलामुखी अनुष्ठान संपन्न हुआ। ऋषिनगर स्थित बगलामुखी ज्योतिष संस्थान में ज्योतिषाचार्य एवं

बगलामुखी साधक अर्चना सरमंडल द्वारा यह अनुष्ठान किया गया। इस अवसर पर तीन सर्वाथसिद्धि और दो रवि योग के विशेष संयोग में शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही।

एकांतवास में रहकर पूर्ण किया सवा लाख जाप

साधक अर्चना सरमंडल ने बताया कि हर नवरात्रि की तरह इस बार भी उन्होंने एकांतवास में रहकर देवी के सवा लाख मंत्रों का जाप पूर्ण किया। इसके साथ ही उनका 29वां पुरश्चरण भी संपन्न हो गया है। अब तक 29 लाख मंत्रों से देवी की आराधना की जा चुकी है। बुधवार को सप्तमी तिथि की रात्रि में सप्त कुंडीय अनुष्ठान के

माध्यम से इसकी पूर्णाहुति की गई। पूर्णाहुति के अवसर पर देवी से उज्जैन और पूरे देश की सुख-समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना की गई।

जनहित में किया जाता है सिद्धि का प्रयोग

अनुष्ठान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अर्चना सरमंडल ने बताया कि देवी बगलामुखी अष्टम महाविद्या हैं, जो स्वर्ण आसन पर विराजित हैं। वे मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन आदि शक्तियों से सुसज्जित हैं। देवी अपने भक्तों को कभी पराजित नहीं होने देतीं। सर्वत्र विजय, गुप्त शत्रु बाधा और तंत्र-मंत्र निवारण, मान-प्रतिष्ठा प्रीति तथा रोग मुक्ति के लिए देवी बगलामुखी का अनुष्ठान किया जाता है। उन्होंने बताया कि वे हर नवरात्रि में यह साधना करती हैं और सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात इसका उपयोग केवल जनता के हित और कल्याण के लिए किया जाता है।

संपादकीय

अंतरिक्ष बुहारने की जरूरत



दुनिया के एक मशहूर कारोबारी और टेस्ला तथा एक्स (पूर्व में ट्विटर) के मालिक की दूरसंचार कंपनी स्टारलिनक इंटरनेट सर्विसेज फिलहाल करीब सौ देशों को इंटरनेट सेवाएं दे रही है। इस कंपनी की बातचीत भारत से भी चल रही है। उम्मीद है कि यह देश के दूरदराज क्षेत्रों में भी तेज और सस्ती इंटरनेट सेवाएं देने में प्रतिद्वंद्वी कंपनियों से होड़ करेगी। आज इंटरनेट तमाम सुविधाओं का वाहक बन गया है, इसकी बदौलत जो डिजिटल क्रांति आई है, उसने कई कामकाज आसान कर दिए हैं। अब तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक भी इसी इंटरनेट के कंधे पर सवार होकर नए गुल खिला रही है। मगर इसी इंटरनेट के रास्ते कई फर्जीवाड़े भी हो रहे हैं। इनसे पूरी दुनिया परेशान है। एक समस्या इसकी वजह से पैदा हो रहे मानसिक प्रदूषण और डेटा के रूप में जन्म ले रहे कचरे की है, जिस पर ज्यादा विचार नहीं हो रहा है। मगर यह इंटरनेट अब अंतरिक्ष में कचरे की भरमार का कारक भी बन गया है। यानी दूरसंचार क्रांति धरती पर ही अनेक तरह का कबाड़ पैदा नहीं कर रही है, बल्कि अंतरिक्ष में जिन उपग्रहों की बदौलत इंटरनेट हम तक पहुंच रहा है, वे भी समस्याएं बढ़ा रहे हैं।

अंतरिक्ष में कचरा कोई नई समस्या नहीं है। सितारों के निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सारा कचरा पहले ही हमारे नजदीकी अंतरिक्ष में मौजूद रहा है। उसके खतरे पहले से कायम हैं। पर जब से अंतरिक्ष ईसानी गतिविधियों का केंद्र बना है, वहां इस कचरे ने और ज्यादा खतरनाक रूप धर लिया है। हम जिन इंटरनेट पर आज इतने ज्यादा निर्भर हो गए हैं, उसे हम तक पहुंचाने के एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल हो रहे उपग्रह अंतरिक्षीय कबाड़ की बड़ी वजह बन गए हैं। ये उपग्रह अंतरिक्ष में मुख्यतः दो स्थानों पर हैं। एक तो पृथ्वी की निचली कक्षाओं में, जहां खासतौर से अकेले स्टारलिनक ने अब तक 6764 उपग्रह पहुंचा दिए हैं। इनमें से 6714 काम कर रहे हैं, जबकि शेष कबाड़ होकर चक्कर काट रहे हैं। स्टारलिनक की मदद करने वाली एलन मस्क की ही एक और कंपनी स्पेसएक्स की योजना आगामी वर्षों में 42 हजार उपग्रह और भेजने की है, ताकि दुनिया में चप्पे-चप्पे तक इंटरनेट पहुंचाया जा सके। स्टारलिनक ने वर्ष 2019 में अपना पहला दूरसंचार उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था। उसके आले पांच साल में ही उसके उपग्रहों की संख्या साढ़े छह हजार पर गई।

अंतरिक्ष की ऊपरी कक्षाओं में भारत समेत दुनिया के कई देशों के 3135 संचार उपग्रह पहले से ही हैं। अभी तक का आकलन कहता है कि पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 14 हजार से ज्यादा उपग्रह मौजूद हैं, जिनमें से करीब 3500 निष्क्रिय यानी कबाड़ हो चुके हैं। इस कबाड़ पर नजर रखने वाली अमेरिकी संस्था स्लिंगशाट एअरोस्पेस का कहना है कि ये निष्क्रिय उपग्रह कचरा बन गए हैं। इसके अलावा तमाम अन्य अंतरिक्षीय गतिविधियों से हमारे करीबी अंतरिक्ष में बारह करोड़ से ज्यादा छोटे-बड़े मलबे के टुकड़े तेजी से चक्कर काटते लगे हैं। असल में, इसके खतरे दो तरह के हैं। एक जितनी बड़ी संख्या में नए उपग्रह विभिन्न उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं, अचानक किसी दिन वहां मौजूद कचरा उनके रास्ते में आ सकता है और पूरे मिशन को खत्म कर सकता है। दूसरे, जिस तरह की भीड़-पुथी की निचली कक्षा में हो गई है, वहां चक्कर काटते उपग्रहों से ही इस कचरे का विनाशकारी आमना-सामना हो सकता है।

कोई देश यह नहीं बताता कि उसके किस उपग्रह का मकसद क्या है और वह आखिर कितने उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ने वाला है। इसकी वजह यह है कि इन उपग्रहों के दोहरे उपयोग सैन्य और नागरिक दोनों ही हैं। सिर्फ सरकारें नहीं, निजी कंपनियां भी कारोबारी हितों के मद्देनजर इनसे जुड़ी जानकारीयों नहीं बताती हैं। ऐसी स्थितियों का परिणाम क्या हो सकता है, इसकी एक नज्दीक इसी वर्ष जून और अगस्त में मिली थी। जून में एक रूसी उपग्रह विस्फोट के साथ फट गया, तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उससे छिटके कचरे की जद में आने का खतरा पैदा हो गया। इसके बाद अगस्त में अंतरिक्ष में काफी ऊंचाई पर पहुंचा एक चीनी राकेट फटा तो उसके टुकड़े मलबे की शक्ल में अंतरिक्ष में फैल गए।

उ वर्ष 2021 में चीन ने संयुक्त राष्ट्र की अंतरिक्ष संस्था का बताया कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की ही एक इकाई स्टारलिनक इंटरनेट सर्विसेज के उपग्रह दो बार चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के बहुत पास आ गए थे। पहली जुलाई और 21 अक्टूबर 2021 को हुई इन घटनाओं को लेकर चीन ने काफी नाराजगी दिखाई थी। संयुक्त राष्ट्र के अंतरिक्ष मामलों के दफ्तर की वेबसाइट के मुताबिक स्पेसएक्स के उपग्रहों के बेहद नजदीक आ जाने की स्थिति को देखते हुए चीन के अंतरिक्ष स्टेशन में किसी टक्कर से बचने की उपायों को लागू कर दिया था, जिससे इसका कामकाज प्रभावित हुआ था। मसला अकेले चीन के लिए नहीं है। ऐसे मामलों पर नजर रखने वाली वेबसाइट स्लिंगशाट का आकलन है कि पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रहों के अत्यधिक नजदीक आ जाने की घटनाओं में एक साल के अंदर ही 17 फीसद का इजाफा हुआ है। चूंकि इस निचली कक्षा में स्टारलिनक के उपग्रहों का बोलबाला है, इसलिए इसकी मूल कंपनी स्पेसएक्स को टक्कर रोकने वाले कई उपाय खुद करने पड़ते हैं। दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियों को भी ऐसे उपाय करने पड़ रहे हैं। जैसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि बीते एक साल में उसके उपग्रहों को टकराव रोकने के लिए औसत से तीन या चार गुना ज्यादा उपाय करने पड़े हैं। प्राकृतिक गतिविधियों पर हमारा कोई वश नहीं, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण अंतरिक्ष में पैदा हो रहे कचरे की रोकथाम कुछ अर्थों में जरूर संभव है। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल का सुझाव है कि इसानी गतिविधियों से अंतरिक्ष में पैदा हो रहे कबाड़ को रोकने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक साथ लाकर कोई तालमेल बनाया जाए। मगर समस्या यह है कि ज्यादातर देश अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर गोपनीयता बरतते हैं।

निजी अंतरिक्ष एजेंसियां भी तकनीक के चोरी होने के भय से आंकड़े साझा नहीं करतीं। इसके अलावा चूंकि लंबी दूरी की बहुराष्ट्रीय मिसाइलों के निर्माण और जासूसी के काम में उपग्रहों का इस्तेमाल अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए इन कार्यक्रमों का सटीक डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाता। एक दूसरे पर अविश्वास की इस स्थिति में कोई बदलाव तभी संभव है, जब संयुक्त राष्ट्र इसमें दखल दे। जाहिर है कि जब तक ऐसा नहीं होता, अपने घर को भीतर से बुहारने वाली और सारा कचरा दरवाजे से अंतरिक्ष में पैदा हो रहे कबाड़ को रोकने के लिए अंतरिक्ष की बिगड़ती सेहत एक समस्या ही बनी रहेगी।

शिक्षा में इंटरैक्टिव शिक्षण की परिवर्तनकारी भूमिका

यह आधुनिक दृष्टिकोण सिर्फ शिक्षण रणनीतियों में बदलाव नहीं है बल्कि भविष्य के कार्यबल की गतिशील मांगों के लिए छात्रों को तैयार करने की दिशा में एक छलांग है तकनीकी प्रगति और एआई के एकीकरण के साथ शिक्षा का परिदृश्य महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है, जिससे इंटरैक्टिव शिक्षण एक पसंदीदा दृष्टिकोण बन गया है। क्योंकि इंटरैक्टिव लर्निंग जुड़ाव, आलोचनात्मक सोच और दीर्घकालिक स्मृति को बढ़ावा देती है, इससे ज्ञान को अधिक अच्छे तरह से आत्मसात करना संभव हो जाता है। यह निस्संदेह राष्ट्रीय पारंपरिक शिक्षण पर एक सुधार है, जो ज्यादातर रटने पर जोर देता है और काफी हद तक पाठ्यपुस्तक-आधारित तकनीकों पर निर्भर करता है। आज के गतिशील वातावरण में आवश्यक योग्यताएँ इंटरैक्टिव सीखने के लिए बेहतर अनुकूल हैं। पारंपरिक शिक्षण दृष्टिकोण का उपयोग करके ज्ञान को निष्क्रिय रूप से अवशोषित करने से सतही शिक्षा प्राप्त होती है, जो अंततः प्रतिकूल होती है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं के शोध के अनुसार, पढ़ने और व्याख्यान जैसी निष्क्रिय सीखने की तकनीकों में याद रखने की दर केवल 5-10 प्रतिशत है। इंटरैक्टिव लर्निंग का आगमन-इंटरैक्टिव लर्निंग द्वारा एक अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान किया जाता है, जो प्रौद्योगिकी, टीम वर्क और

वास्तविक दुनिया की समस्या-समाधान को जोड़ता है। इससे जुड़ाव बढ़ता है और प्रतिधारण बढ़ता है। डिजिटल उपकरण, परियोजना-आधारित शिक्षा और समूह चर्चा सभी इस दृष्टिकोण के दायरे में शामिल हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार, इंटरैक्टिव कक्षाओं के छात्रों ने परीक्षाओं में पारंपरिक व्याख्यान देने वाले छात्रों से 6 प्रतिशत बेहतर प्रदर्शन किया। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे इंटरैक्टिव शिक्षण दृष्टिकोण पारंपरिक रणनीतियों से बेहतर काम करते हैं।

1. बड़ी हुई अवधारणा- राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं के शोध के अनुसार, अभ्यास-दर-करने और समूह चर्चा जैसी सक्रिय सीखने की रणनीतियों में उच्च अवधारण दर थी, जो 50 से 75 प्रतिशत तक थी। छात्र व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से एसटीईएम सिद्धांतों को सीधे लागू कर सकते हैं। अमेरिकन सोसाइटी फॉर इंजीनियरिंग एजुकेशन के शोध के अनुसार, जिन विद्यार्थियों ने इंटरैक्टिव एसटीईएम गतिविधियों में भाग लिया, उन्होंने मानक निर्देश प्राप्त करने वालों की तुलना में बहुत अधिक सीखा।

2. आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना- इंटरैक्टिव शिक्षण छात्रों को अन्य दृष्टिकोणों की जांच करने और प्रश्न पूछने की अनुमति देकर व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान किया जाता है, जो प्रौद्योगिकी, टीम वर्क और



के शोध के अनुसार, इंटरैक्टिव शिक्षण वातावरण छात्रों की व्यस्तता को बढ़ाते हुए और उत्पादक सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देते हुए महत्वपूर्ण सोच और प्रतिबिंब को बढ़ावा देता है। छात्र जुड़ाव का एक और व्यापक तरीका गेमिफिकेशन है, जो चुनौतीपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए छात्रों के प्रोत्साहन को बढ़ाता है और गहन सीखने को अनुमति देता है।

3. वास्तविक-विश्व अनुप्रयोग- परियोजना-आधारित शिक्षा, जो शिक्षा को वास्तविक दुनिया के मुद्दों से जोड़ती है और व्यावहारिक संदर्भों में जानकारी को प्रयोज्यता को बढ़ाती है, इंटरैक्टिव शिक्षा का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

एडुटोपिया के 2022 के शोध के अनुसार, पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके अध्ययन करने वाले छात्रों के विपरीत, प्रोजेक्ट-आधारित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों ने वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में जानकारी के बेहतर अनुप्रयोग का प्रदर्शन किया।

4. भविष्य के लिए तैयार अधिक आकर्षक और प्रासंगिक निर्देश के माध्यम से, इंटरैक्टिव शिक्षण छात्रों को पारंपरिक तरीकों की तुलना में बाधाओं को अधिक प्रभावी ढंग से दूर करने में सक्षम बनाता है। अनिश्चित और लगातार बदलते समय के लिए छात्रों को शिक्षित करने के लिए शिक्षा को समस्या-समाधान, टीम वर्क

और आज के प्रतिस्पर्धी श्रम में लचीलेपन जैसी क्षमताओं पर जोर देना चाहिए। इंटरैक्टिव दृष्टिकोण भी प्रेरणा को बढ़ावा देते हैं और टीम वर्क को प्रोत्साहित करते हैं, जो छात्रों को उनकी संचार और टीम वर्क क्षमताओं को निखारने में सहायता करता है। EdTechXGlobal के अनुसार, वैश्विक एडटेक बाजार 2025 तक 404 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। जो छात्र इंटरैक्टिव शिक्षण तकनीक का उपयोग करते हैं वे न केवल अकादमिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं बल्कि वास्तविक दुनिया में समस्याओं से निपटने के लिए भी बेहतर तैयार होते हैं।

हरित क्रांति की अनचाही विरासत



हरित क्रांति ने देश की किस्मत बदलने में महती भूमिका निभाई, लेकिन अब इसका चक्र उल्टा घूम रहा है। इसके दुष्परिणाम उस समय नीति निर्माताओं ने सोचे भी नहीं होंगे। आज जब किसान आए दिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सीमाओं पर डेरा डाल रहे हैं तो 1960 के दशक की हरित क्रांति के परिणाम अपयोजित बिजली आपूर्ति, पानी का संकट, लगातार गिरती मिट्टी की गुणवत्ता, वायु प्रदूषण और तेजी से बढ़ती मुफ्त योजनाओं की संस्कृति जैसे बड़े संकट के रूप में सामने आ रहे हैं।

हरित क्रांति ने भारत को जहां अकाल के जबड़े से बाहर निकाला वहीं, सार्वजनिक कानून अथवा अमेरिका से आयातित पीएल 480 गेहूं पर निर्भरता जैसे अपमान से बचाया और हमेशा तंगदस्ती में जीवन गुजारने वाले हालात से बाहर निकाला। दुर्भाग्य से जिन नीतियों ने हरित क्रांति को सफलता के शिखर पर पहुंचाया, वे ही आज न चाहते हुए भी तुकसानदेह साबित हो रही हैं और केंद्रीय सत्ता उनसे बचाव के उपाय ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही है।

ये संकट सरकार द्वारा किसानों को अधिक से अधिक गेहूं एवं चावल की फसलें उगाने के लिए शुरू की गई मुफ्त बिजली, सब्सिडी पर उर्वरक और एमएसपी की गारंटी अथवा आधिकारिक मंडियों में उपज बेचने का प्रावधान जैसी प्रोत्साहन योजनाएं हैं, जो आज असहनीय बोझ बन रहे हैं। एमएसपी को ही ले लें। उपज को बाजार दर पर खरीदने की यह व्यवस्था किसानों को व्यापारियों के उत्पीड़न या शोषण का शिकार होने से बचाने के लिए लायी गई थी। लेकिन, शक्तिशाली किसान लॉबी के दबाव में लगातार इसे आगे बढ़ाया गया और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अब अधिकतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का रूप ले चुकी है। आज सरकार देश में वार्षिक स्तर पर पैदा होने वाले कुल गेहूं और चावल का 30 से 40 प्रतिशत तक एमएसपी पर खरीद रही है। देश में 22 अनाज फसलें भी एमएसपी के दायरे में आती हैं, लेकिन सरकार उन्हें न के बराबर ही खरीदती है। कभी-कभी राज्य सरकारें एमएसपी पर भी प्रीमियम देती हैं। मध्य प्रदेश इसका एक उदाहरण है। इस व्यवस्था से सरकारों की परेशानी और बढ़ जाती है।

फसलों की बिक्री के लिए एमएसपी जैसी नीतियों का बड़े किसानों ने खूब फायदा उठाया और सीमांत या छोटे किसान

जल की जरूरत पड़े। लेकिन, इसका परिणाम यह हुआ कि फसल देर से कटने लगी और आगे रबी की फसल बोने को खेत खाली करने के लिए किसानों के पास समय ही नहीं बचता। इसके लिए उन्होंने सस्ता और जल्दी वाला समाधान ढूँढ निकाला और वे धान की पराली को खेतों में ही जलाने लगे, लेकिन इससे वायु प्रदूषण के रूप में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया। इसी प्रकार उर्वरकों का मामला है, जिसने खेती पर और गंभीर दुष्प्रभाव डाले हैं। वार्षिक स्तर पर कुल उर्वरकों पर दी जाने वाली 1.88 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी का दो-तिहाई केवल यूरिया पर खर्च होती है। इसने इस मूल्य नियंत्रित उर्वरक के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा दिया है, जिससे मिट्टी की पोषकता में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। लगभग एक दशक से यूरिया की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। इसका परिणाम यह हुआ कि किसान पोटेशियम और फॉस्फेट के बजाय यूरिया का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं।

हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में बताया गया है कि पंजाब खेती में अपनी आवश्यकता से 61 प्रतिशत अधिक यूरिया उपयोग कर रहा है। इस लेख में कहा गया है, 'यह बहुत ही हास्यास्पद है कि यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी अनाज की उपज बढ़ाने से ज्यादा वातावरण में जहर डाल रही है।' आजादी के फौरन बाद कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों ने किसानों को मुफ्त या उदार सब्सिडी पर बिजली उपलब्ध करानी शुरू की थी। इसका सीधा प्रभाव दिवालिया होती राज्य स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर देखा जा सकता है और जिन्होंने अपने वित्तीय संकट से निपटने के लिए काफी संघर्ष किया। पैसे की कमी के कारण वे अपने आधारभूत ढांचे को उन्नत नहीं कर सके। नतीजतन जब बिजली की मांग चरम पर होती है तो वे हाथ खड़े कर देते हैं।

लंबे समय तक बिजली कटौती के कारण उद्योग वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा तैयार तथा करदाताओं की ओर से वित्तपोषित पांच बेलआउट पैकेज भी नाकामी साबित हुए और विद्युत व्यवस्था की तस्वीर नहीं बदली। तमाम वित्तीय समर्थन के बावजूद आज खेती हजारों छोटे किसानों के लिए घाटे का सौदा बन गई है। सरकार द्वारा भारतीय उपभोक्ताओं के हितों के लिए व्यापारियों पर आवधिक नियंत्रण और किसानों को वित्तीय सहयोग की योजनाओं ने हालात को और खराब बना दिया है।

मोदी सरकार ने इसका हल प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी के तौर पर निकाला था, जो सीधे उनके खाते में जाती है। हरित क्रांति से संबंधित मुफ्त योजनाओं की तरह ही इस वित्तीय सहायता वाली सब्सिडी योजना को वापस लेना भी असंभव होगा, जो मुसीबत को और बढ़ाएगा ही।

गिरते भूजल स्तर को संभालने के लिए वर्ष 2009 से धान की रोपाईं को मॉनसून सीजन के साथ शुरू किया गया, ताकि वर्षा जल से सिंचाई और कम से कम भूगर्भीय

संविधान ने दी देश को दिशा



भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित विशेष चर्चा में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सभा में यह उचित ही कहा कि संविधान ने आजादी के बाद भारत के लिए सभी पूर्वानुमानित संभावनाओं को हासिल किया है। एक युवा गणतंत्र के जीवन में उतार-चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन भारतीय संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है और उसने भारत की अच्छी सेवा की है। इसकी सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण सत्ता का निरंतर शांतिपूर्ण हस्तांतरण है, जो जनाकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि भारत में हर स्तर पर राजनीति बेहद प्रतिस्पर्धी है। पिछले दशकों में देश में कई तरह के राजनीतिक दलों और गठबंधनों ने शासन किया है। कुछ विफलताओं को छोड़ दें तो वे ज्यादातर समय देश को आगे ले गए हैं। साल 1975 में आपातकाल लागू करना ऐसा ही एक स्पष्ट उदाहरण है। भारत के संविधान को एक गतिशील और जीवंत दस्तावेज के रूप में पेश किया गया था जिसमें एक युवा राष्ट्र की बदलती ज़रूरतों को अनुकूल लचीलापन निहित था। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे संविधान में 100 से ज्यादा बार संशोधन किए गए। उदाहरण के लिए सबसे हाल का संशोधन संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का था, हालांकि यह प्रावधान अगले परिसीमा के बाद ही लागू हो सकेगा। अगर आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों ने कराधान की अपनी साझा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वस्तु एवं सेवा कर को लागू करना संभव बनाया और इसके लिए संविधान में प्रासंगिक बदलाव किए गए। इस तरह संविधान ने पिछले वर्षों में भारत को सामाजिक और आर्थिक, दोनों तरह के हितों को आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। वैसे तो पिछले हफ्ते संसद में आयोजित दो दिवसीय चर्चा में विभिन्न पहलुओं को छुआ गया, लेकिन कई स्तरों पर यह एकतरफा रही। हालांकि, यह पूरी तरह से अप्रत्याशित भी नहीं था, लेकिन सदस्य इस अवसर को इस्तेमाल इस पर चर्चा के लिए कर सकते थे कि संविधान में अंगीकृत किए गए विचारों पर आगे किस तरह से अमल हो।

भारत साल 2047 यानी स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में काम कर रहा है, इसलिए यह उचित ही है कि इसका उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन में परिवर्तन लाना और उन्हें सशक्त बनाना हो। इस संबंध में मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाले कुछ प्रावधानों की चर्चा करना मुनासिब होगा। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 14 भारतीय क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या सभी को कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान किसी भी तरह के भेदभाव को खारिज करता है।

हालांकि भारतीय राज्य सभी नागरिकों को यह गारंटी उपलब्ध कराने में अक्षम साबित हुआ है। उदाहरण के लिए हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने तक, कई राज्यों में 'बुलडोजर न्याय' चल रहा था जो कि संविधान के शब्दों और भावनाओं, दोनों के खिलाफ था। भारत को संस्थाओं, शासकों पर न्यायपालिका को मजबूत करने की जरूरत है। बड़ी संख्या में लंबित मुकदमों की वजह से फैसले होने में काफी देरी होती है जिससे आम नागरिकों के हित और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों में इसे लेकर आमरण है कि भारत को अपर विकसित देश बनाना है तो उसे बेहतर गुणवत्ता वाली मानव संपदा की जरूरत होगी। इस संदर्भ में संसद ने अनुच्छेद 21ए (86वां संशोधन) को अपनाकर अच्छा कदम उठाया है जिसके जरिये राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करेगा। इसका नतीजा यह है कि पिछले वर्षों में स्कूलों में नामांकन बढ़ गया है जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही श्रेय की हकदार हैं। हालांकि हाल के कई सर्वेक्षणों, खासकर वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (असर) में यह साफ हुआ है कि शिक्षा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है।

सुबह होते ही पेट्रोल-डीजल के 61 टैंकर रवाना, पंपों पर पहुंचे अधिकारी, प्रशासन ने थामा मोर्चा



इंदौर। इंदौर में कल शाम से पेट्रोल पंपों पर लगी भीड़ ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। कल रात में ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मैदान में उतर गए और व्यवस्थाएं संभाली। आज सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तैनात हैं और यह देख रहे हैं कि किसी भी तरह से पेट्रोल और डीजल को लेकर परेशानी न बड़े।

पेट्रोल पंपों को देर रात तक खुले रहने के निर्देश- इंदौर के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेट्रोल-डीजल की निर्बाध

आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। प्रशासन के निर्देश पर जिले के कई पेट्रोल पंपों को देर रात तक लगातार खुले रखा गया, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। एडीएम सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों, पुलिस अधिकारी, आपूर्ति विभाग और राजस्व विभाग की टीमों ने देर रात तक पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। अधिकारियों द्वारा स्वयं फील्ड में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और पेट्रोल-डीजल वितरण की सतत मॉनिटरिंग की गई। सभी पंप संचालकों को निर्देश दिए गए कि वे निर्धारित समय से अधिक देर तक पंप खुले रखें और उपभोक्ताओं को सुचारु रूप से

ईंधन उपलब्ध कराएं। सुबह से मांगलिया से निकले ट्रक-जिला आपूर्ति नियंत्रक एम. एल. मारु ने बताया कि जिले में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। वर्तमान में जिले में प्रतिदिन लगभग 10 लाख लीटर पेट्रोल और 15 लाख लीटर डीजल की खपत होती है, जबकि पंपों पर करीब 42 लाख लीटर पेट्रोल और 65 लाख लीटर डीजल का स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा मांगलिया डिपो से लगातार ईंधन की आपूर्ति भी जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में पेट्रोल-डीजल की किसी प्रकार की कमी नहीं है। आम उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकता अनुसार ही ईंधन भरवाएं।

मांगलिया डिपो से पेट्रोल-डीजल के 61 टैंकर रवाना* इंदौर जिले में पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और सुचारु बनी हुई है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर आज सुबह 6 बजे से मांगलिया स्थित एचपीसीएल, भारत पेट्रोलियम एवं

इंडियन ऑयल के डिपो पर टैंकरों में ईंधन भरने का कार्य तेज गति से प्रारंभ कर दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 8 बजे तक मांगलिया डिपो से हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 25 टैंकर लोरियां, भारत पेट्रोलियम की 17 तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की 19 टैंकर लोरियां विभिन्न पेट्रोल पंपों के लिए रवाना हो चुकी हैं। डिपो पर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध है और पूरी क्षमता के साथ टैंकरों को भरा जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम सुबह 5 बजे से ही सक्रिय होकर मांगलिया डिपो तथा फोल्ड के पेट्रोल पंपों का सतत निरीक्षण कर रही है, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही पेट्रोल-डीजल प्राप्त करें। जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है तथा आपूर्ति पूरी तरह व्यवस्थित रूप से जारी है।

भारी सुरक्षा के बीच नारायण साई की फैमिली कोर्ट में पेशी, तलाक केस में एक घंटे चली सुनवाई



इंदौर। इंदौर की फैमिली कोर्ट में दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे नारायण साई को कोर्ट पेश किया गया। गुजरात पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लेकर पहुंचा। उनकी पत्नी जानकी द्वारा दायर किए गए तलाक और भरण-पोषण के मामले में यह सुनवाई हुई।

नारायण साई वर्तमान में सूरत की जेल में बंद है। सोमवार दोपहर गुजरात पुलिस उसे इंदौर लेकर आई। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार की

अप्रिय स्थिति न बने। पुलिस नारायण साई को सीधे कोर्ट रूम के भीतर ले गईं। इस दौरान कोर्ट के बाहर आसाराम के अनुयायियों की भारी भीड़ जमा थी, जिसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। सुनवाई के दौरान मुख्य मुद्दा पत्नी जानकी को दिए जाने वाले भरण-पोषण का रहा। साल 2018 में कोर्ट ने नारायण साई को आदेश दिया था कि वह अपनी पत्नी को 50 हजार रूपए प्रति माह की राशि प्रदान करें। लंबे समय से राशि न मिलने

के कारण अब यह आंकड़ा ब्याज समेत 55 लाख रूपए से अधिक हो चुका है। नारायण के वकीलों ने मई 2025 में इस मामले को रि-ओपन करने की याचिका लगाई थी। उनका तर्क है कि जब कोर्ट ने पूर्व में यह आदेश दिया था, तब नारायण जेल में था और उसका पक्ष ठीक से नहीं सुना गया था।

एक घंटे तक चली सुनवाई- नारायण और जानकी का विवाह वर्ष 1995 में हुआ था। मूल रूप से भोपाल की रहने वाली जानकी ने करीब 4 साल पहले इंदौर कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। पिछली कई सुनवाइयों में नारायण के उपस्थित न होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था, जिसके बाद सोमवार को उसे पेश किया गया। करीब एक घंटे से अधिक समय तक चली इस सुनवाई के बाद पुलिस उसे पुनः सूरत जेल के लिए लेकर रवाना हो गई।

त्यावसायिक इमारतों को इस वजह से दिया नोटिस; बेसमेंट से बाजार हटाने का सख्त फरमान

इंदौर। इंदौर नगर निगम द्वारा शहर की व्यावसायिक इमारतों के तलघर में चल रही व्यापारिक गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा गया है। निगम प्रशासन ने शहर की ऐसी 35 प्रमुख बिल्डिंगों को चिन्हित किया है, जहां बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के स्थान पर दुकानों या अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा रहा था। इन सभी भवन स्वामियों को औपचारिक नोटिस जारी कर सख्त हिदायत दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर नियमों का पालन सुनिश्चित करें। दस दिनों के भीतर पार्किंग व्यवस्था बहाल करने के निर्देश-



नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा जारी किए गए इन नोटिसों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भवन संचालकों को 10 दिन का समय दिया जा रहा है। इस अवधि के भीतर उन्हें तलघर में किए गए अवैध व्यावसायिक निर्माण को हटाना होगा और वहां पार्किंग की व्यवस्था को फिर से सुचारु करना होगा। निगम के अधिकारियों ने साफ किया है कि यदि इस समय

सीमा के बाद भी भवनों में पार्किंग की जगह व्यापारिक गतिविधियां संचालित पाई गईं, तो निगम की टीम स्वयं वहां पहुंचकर निर्माण कार्य को ध्वस्त करने की सीधी कार्रवाई करेगी।

हर साल चलने वाले अभियान की सार्थकता पर सवाल- उल्लेखनीय है कि इंदौर नगर निगम द्वारा बेसमेंट की जांच और नोटिस देने की यह प्रक्रिया हर एक या दो साल में दोहराई जाती है। विभागीय रिकॉर्डों के अनुसार, हर बार भवन अधिकारियों और भवन निरीक्षकों द्वारा जोनल स्तर पर इमारतों की सघन जांच की जाती है और नोटिस भी बांटे जाते हैं। हालांकि, स्थानीय नागरिकों और जानकारों

का कहना है कि इन अभियानों का परिणाम अक्सर सिफर ही रहता है। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद कार्रवाई ठंडी पड़ जाती है, जिससे पार्किंग की समस्या जस की तस बनी रहती है। जोनल कार्यालयों में सक्रिय हुए भवन अधिकारी और निरीक्षक वर्तमान में नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा के निर्देशों के बाद सभी जोनल कार्यालयों में तैनात भवन अधिकारी और भवन निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों की इमारतों का सर्वे कर रहे हैं। इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि किन इमारतों ने भवन अनुज्ञा के समय पार्किंग के लिए जगह मंजूर करवाई थी लेकिन बाद में वहां व्यावसायिक निर्माण कर लिया।

ब्रेनडेड के बाद 34 साल के इंजीनियर ने दी 3 लोगों को नई जिंदगी, इंदौर में बना 67वां ग्रीन कॉरिडोर

इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मानवता की एक मिसाल पेश की गई है जहां ब्रेन हेमरेज के कारण ब्रेनडेड घोषित किए गए शुजालपुर के एक 34 वर्षीय युवक के परिजन ने अंगदान का साहसिक निर्णय लिया। इस परोपकारी कार्य के चलते दो महिलाओं सहित तीन जरूरतमंद मरीजों को नई जिंदगी मिलना संभव हो सका। संस्था मुस्कान द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार ब्रेनडेड घोषित किए गए अंगदानी युवक की एक किडनी और एक लिंवर सीएचएल हॉस्पिटल में उपचारधीन दो महिला मरीजों को प्रत्यारोपित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त युवक की दूसरी किडनी का प्रत्यारोपण शैल्वी हॉस्पिटल में भर्ती एक पुरुष मरीज में किया जाएगा।



अंगों को समय पर संबंधित अस्पतालों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए इंदौर पुलिस और प्रशासन के सहयोग से ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया गया। सीएचएल अस्पताल से शैल्वी अस्पताल तक किडनी पहुंचाने के लिए बनाया गया यह रास्ता इंदौर शहर का अब तक का 67वां ग्रीन कॉरिडोर साबित हुआ। सेवादार अर्थ ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शुजालपुर के रहने वाले 34 वर्षीय अनुपम, जिनके पिता का नाम जगदीश नालम है, उन्हें गंभीर ब्रेन हेमरेज की शिकायत के बाद सीएचएल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

उपचार के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने गहन परीक्षण के बाद अनुपम को ब्रेनडेड घोषित कर दिया था। मुस्कान अर्थ के मुताबिक पेशे से इंजीनियर अनुपम नालम के परिवार ने संभावित अंगदान की प्रक्रिया के लिए मुस्कान रूपा के सेवादारों से संपर्क साधा था। सकारात्मक काउंसिलिंग और परिवार की इच्छाशक्ति के कारण अंगदान की आधिकारिक मंजूरी प्राप्त हुई। इस पुनीत कार्य में दिवंगत के पिता जगदीश, बुआ डॉ वार्धा और भाइयों अनुराग व जुबीन नालम का विशेष सहयोग रहा। इधर, अंगदान के बाद युवक का शव जब गृह नगर पहुंचा तो लोगों ने शय्यात्रा पर पुष्पवर्षा की और हवाओं लोगों ने तालियां बजाकर अंगदान के निर्णय का सम्मान किया। वहीं प्रशासन ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया।

राज्यपाल श्री पटेल मुद्दयमंत्रि दुधारू पशु प्रदाय योजना के हितग्राहियों को पशुओं की देंगे सौगात



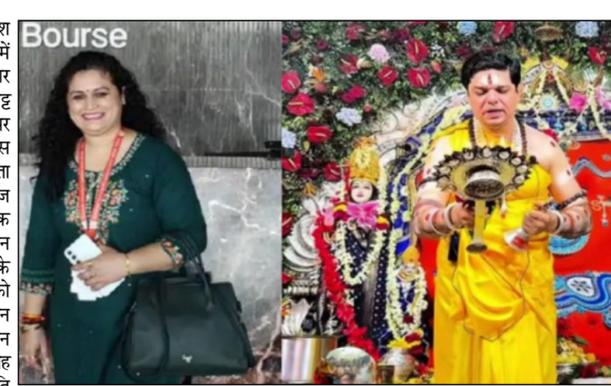
भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के हितग्राहियों को दुधारू पशुओं की सौगात देंगे। कार्यक्रम मंडला जिले के विकासखंड बिडिया के ग्राम कान्हारी कला में होगा। कार्यक्रम में पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री लखन पटेल भी उपस्थित रहेंगे। बुधवार को पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री

पटेल ने लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल श्री पटेल से भेंट की। उन्होंने आगामी 1 अप्रैल को मंडला जिले के विकासखंड बिडिया के ग्राम कान्हारी कला में होने वाले मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना कार्यक्रम के बारे में राज्यपाल श्री पटेल को जानकारी दी और उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। राज्यपाल श्री पटेल ने आमंत्रण को स्वीकार करते हुए कार्यक्रम

में शामिल होने की सहमति प्रदान की। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव भी उपस्थित रहे। प्रदेश सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातीय बैगा, सहरीया एवं भारिया समुदाय के समग्र विकास, आर्थिक सशक्तिकरण के लिये मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना संचालित की जा रही है। योजना में प्रदेश सरकार द्वारा हितग्राही को इकाई लागत का 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जबकि 10 प्रतिशत राशि हितग्राही को जमा करनी होती है। योजना का क्रियान्वयन डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योपुर, मुसैन और भिंड जिले में किया जा रहा है।

खजराना गणेश मंदिर के पुजारी पर दहेज के आरोप, एक करोड़ रुपए और कार मांगी

इंदौर। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर से जुड़े एक प्रतिष्ठित परिवार में पारिवारिक विवाद सामने आया है। परिवार की बहू इंदिरा भट्ट ने अपने पति पुनीत भट्ट और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त कार्यालय में गुहार लगाई है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसे दहेज के लिए न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बल्कि जबर्न घर से भी निकाल दिया गया है। इंदिरा के मुताबिक उनकी शादी 17 मई 2025 को संपन्न हुई थी। उन्होंने बताया कि यह उन दोनों की दूसरी शादी थी और पति ने संतान प्राप्ति की इच्छा के चलते उनसे विवाह किया था। शुरुआती दो महीनों तक स्थिति सामान्य रही लेकिन जुलाई 2025 के बाद ससुराल वालों का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। आरोप है कि पति, सास, ननद, नंदी और देवरों ने मिलकर उन पर मायके से 1 करोड़ रुपए नकद और एक फॉर्च्यूनर कार लाने का दबाव बनाया शुरू कर दिया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में अत्यंत मार्मिक आरोप लगाए हैं। इंदिरा का कहना है कि ससुराल में उन्हें कई बार भोजन तक नहीं दिया जाता था और उन्हें घर के भीतर



ही बंद करके रखा जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने से रोकने के लिए नौकरी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। जब भी उन्होंने इन बातों का विरोध किया, तो उनके पति उन्हें अलग कमरे में ले जाकर धमकाते थे। इंदिरा का दावा है कि उनके ससुराल पक्ष ने उनके कीमती जेवर भी लूटे और लगभग 5 लाख रुपए नकद भी अपने कब्जे में ले लिए हैं और मांगने पर उनके

साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। दत्तक पुत्र की पत्नी के गर्भवती होने पर बदला व्यवहार- शिकायत पत्र में इंदिरा ने एक विशेष घटनाक्रम का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि उनके पति पुनीत भट्ट की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने बड़े पिता के पुत्र उदित को गोद लिया था। शादी के शुरुआती समय में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही जुलाई 2025 में यह सूचना मिली कि दत्तक पुत्र उदित की पत्नी

गर्भवती है, वैसे ही ससुराल वालों का रवैया इंदिरा के प्रति क़रूर हो गया। आरोप है कि इसके बाद से ही 1 करोड़ रुपए और महंगी कार की मांग तेज कर दी गई और स्पष्ट कहा गया कि यह मांग पूरी होने पर ही उन्हें शांति से रहने दिया जाएगा। बूटे मुकदमों में फंसाने की साजिश- इंदिरा भट्ट ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई। उनके पति के दत्तक पुत्र उदित ने अपनी पत्नी के माध्यम से इंदिरा पर गलत आरोप लगाकर एक मामला दर्ज करवाया, जिसमें खजराना पुलिस ने कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया है। पीड़िता का कहना है कि यह सब उन्हें परेशान करने और दबाव में लाने के लिए किया गया है। सितंबर 2025 में मारपीट कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद से वह अपने मायके में रहने को विवश हैं। ससुराल पक्ष अब उन्हें अपने प्रभाव का डर दिखाकर पुलिस कार्रवाई न होने देने की धमकी दे रहा है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आवेदन प्राप्त हो गया है और जांच के बाद उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री श्री टेटवाल ने सारंगपुर में विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की

भोपाल। मंत्री श्री टेटवाल ने सारंगपुर में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों, आधारभूत संरचना, जल संरक्षण और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का समग्र मूल्यांकन किया। बैठक में विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की विभागीय समीक्षा करते हुए प्रशासनिक दक्षता, समयबद्धता और गुणवत्ता को केन्द्र में रखने के निर्देश दिए गए। मंत्री श्री टेटवाल ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्य केवल स्वीकृतियों तक सीमित न रहें, बल्कि धरातल पर परिणाम दिखाई दें। सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हों, पूर्ण परियोजनाओं का त्वरित हस्तान्तरण हो और उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने दोहराया कि लापरवाही या अनावश्यक विलंब की स्थिति में जवाबदेही तय की जाएगी। जल संरक्षण को दी रणनीतिक दिशा- जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत संचालित जल संचनात्मक कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री गौतम टेटवाल ने



वर्षा जल संचयन, नाला उपचार और भू-जल संवर्धन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को जनांदोलन का स्वरूप देना आवश्यक है, जिससे दीर्घकालीन जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नदियों के पुनर्जीवन और श्रमदान आधारित पहलों में व्यापक जनसहभागिता पर बल दिया गया। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और अनुशासन- पेयजल, शिक्षा एवं अन्य

संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया। कृषि और पर्यावरण संचालन पर विशेष फोकस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, किसानों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों के विस्तार पर जोर दिया गया। नरवाई जलाने पर रोक के लिए प्रभावी जागरूकता अभियान संचालित करने और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। 'हरित

सारंगपुर' के लक्ष्य के अंतर्गत व्यापक पौधारोपण को सामाजिक दायित्व के रूप में अपनाने का आह्वान किया गया। जनसेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश- बैठक में विद्युत, स्वास्थ्य और पेयजल सेवाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक संस्थानों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा टीकाकरण जैसे अभियानों को गति देने के निर्देश दिए गए। ग्रीष्मकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पेयजल स्रोतों की मरम्मत, संरक्षण और वैकल्पिक व्यवस्थाओं की अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही आगामी सामूहिक विवाह एवं निकाह कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर सभी व्यवस्थाएं गरिमापूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री गौतम टेटवाल ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की मूल प्रतिबद्धता है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे समन्वित, पारदर्शी और परिणाम आधारित कार्यसंस्कृति के माध्यम से विकास की गति को रथायी और प्रभावी स्वरूप दें।

लोकभवन राज्य की प्रशासनिक गरिमा का प्रतीक- राज्यपाल श्री पटेल

सुदृढ़ीकरण, सौंदर्यीकरण, सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए कार्य किए गए हैं, जिससे लोकभवन परिसर का स्वरूप और अधिक आकर्षक, सुरक्षित और सुविधाजनक हुआ है। गांधी जयंती पर हुआ था प्रवेश द्वार क्र.- 1 का लोकार्पण- राज्यपाल श्री पटेल ने अप्रैल 2025 में लोकभवन के प्रवेश द्वार क्रमांक- 1 एवं 2 के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का भूमि-पूजन किया था। उन्होंने पूजा-अर्चना कर निर्माण कार्य की आधारशिला रखी थी। राज्यपाल श्री पटेल लोकभवन के प्रवेश द्वार क्र.- 1 के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों के बाद विगत वर्ष गांधी जयंती के अवसर पर उसका लोकार्पण किया था। उसके बाद प्रवेश द्वार क्रमांक-2 का सुदृढ़ीकरण कार्य प्रारंभ हुआ।

पहचान को भी सशक्त करता है। उन्होंने राज्य की सांस्कृतिक विशिष्टताओं के अनुरूप गेट निर्माण के लिए संबंधित विभागों की सराहना की। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी मौजूद थे। लोकभवन के प्रवेश द्वार क्रमांक- 1 एवं 2 के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की पूर्णता तक लगभग 98 लाख 65 हजार रूपयों की लागत आई है। प्रवेश द्वारों की संरचनात्मक

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि लोकभवन प्रदेश की प्रशासनिक गरिमा का प्रतीक है। प्रवेश द्वारों का सुदृढ़ और सुव्यवस्थित होना सुरक्षा के साथ ही राज्य की सांस्कृतिक स्थापत्य

Crude Oil संकट के बीच बड़ी राहत! भारत ने रूस से खरीदा 6 करोड़ बैरल तेल

नई दिल्ली (एजेंसी)। मिडिल ईस्ट तनाव के चलते कुरुड स्पलाई पर दबाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है। देश की रिफाइनरियों ने अप्रैल डिलीवरी के लिए रूस से करीब 6 करोड़ बैरल (60 मिलियन बैरल) कच्चा तेल खरीदा है, जिससे स्पलाई की चिंता काफी हद तक कम हो गई है।

जानकारी के मुताबिक, ये तेल ब्रेट के मुकाबले 5 से 15 डॉलर प्रति बैरल प्रीमियम (करीब 470 रुपए से 1410 रुपए प्रति 158 लीटर) पर खरीदा गया है।

खरीदारी का यह स्तर मार्च के बराबर है, लेकिन फरवरी के मुकाबले दोगुना से ज्यादा



है। यानी भारत ने तेजी से अपनी खरीद बढ़ाकर संभावित कमी को पहले ही संभाल लिया है।

अमेरिका से मिली स्पेशल ड्यूट- इस बड़े फैसले के पीछे एक अहम वजह अमेरिका की

तरफ से मिला स्पेशल वेवर (ड्यूट) है। अमेरिका ने भारत को उन रूसी कार्गो को लेने की अनुमति दी थी, जो 5 मार्च (बाद में 12 मार्च) से पहले जहाजों पर लोड हो चुके थे। इसका मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट में बाधा के कारण पैदा हुई स्पलाई कमी को संतुलित करना था।

हॉर्मुज स्ट्रेट पर आवाजाही प्रभावित- दरअसल, मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही लगभग प्रभावित हो गई है। भारत, जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, ऐसे में

वैकल्पिक स्पलाई पर तेजी से काम कर रहा है। बाजार में लौटी कंपनियों रिपोर्ट के अनुसार, मैंगलोर रिफाइनरी और हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी जैसी कंपनियां, जिन्होंने दिसंबर से रूसी तेल खरीदना कम कर दिया था, अब फिर से बाजार में लौट आई हैं। इससे साफ है कि भारत अब प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हुए सस्ते और उपलब्ध स्रोतों की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ रूस ही नहीं, भारत स्पलाई को डाइवर्सिफाई (खुद 1 इन्वेंट्री) भी कर रहा है। अप्रैल के लिए वेनेजुएला से करीब 80 लाख बैरल तेल खरीदने का अनुमान है, जो अक्टूबर 2020 के बाद सबसे ज्यादा है।

कुल मिलाकर, कुरुड की संभावित कमी के बीच भारत ने समय रहते बड़ा कदम उठाया है। इससे न सिर्फ स्पलाई सुरक्षित होगी, बल्कि आने वाले समय में तेल की कीमतों पर भी राहत मिल सकती है।

पाकिस्तान के सिंध में 15 वर्षीय हिंदू लड़की का अपहरण, मानवाधिकार समूह ने जताई चिंता



डूब गया है। पाकिस्तान में नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण

मानवाधिकार संगठन ने कहा कि पुलिस में मामला दर्ज होने के बावजूद, लड़की कहाँ है, इसका कुछ अता-पता नहीं चला है। सिंधु में हाशिए पर रहने वाले हिंदू समुदायों (मेघवार, भील, और कोल्ही) के लिए मीरान का लापता होना कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि एक दिल दहला देने वाले पैटर्न का हिस्सा है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि ग्रामीण सिंधु में अल्पसंख्यक हिंदू लड़कियों के लिए सुरक्षा कितनी कमजोर हो सकती है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। एक प्रमुख मानवाधिकार समूह ने मंगलवार को पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में 15 वर्षीय हिंदू लड़की के हालिया अपहरण पर चिंता व्यक्त की है, जो इस्लामिक देश में अल्पसंख्यक लड़कियों के प्रति संवेदनहीनता को उजागर करता

है। परिवार और समुदाय के सदस्यों का हवाला देते हुए वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी ने बताया कि मीरान मेघवार का उसके घर से तारेक काउरी और अल्ला डीनो काउरी नाम के दो लोगों अपहरण कर लिया। इससे हिंदू लड़की का परिवार निराशा में

ईरान और अमेरिका में सुलह करवाएगा पाकिस्तान? शहबाज शरीफ बोले - हम तैयार, ट्रंप का क्या आया जवाब



नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान को संभावित वार्ता स्थल के रूप में पेश किया है। उन्होंने कहा कि यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो पाकिस्तान सार्थक और निर्णायक बातचीत की मेजबानी के लिए तैयार है।

पाकिस्तान, मिश्र और एक अन्य खाड़ी राजनयिक के अनुसार, अमेरिका ने पाकिस्तान में वार्ता में शामिल होने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। मध्यस्थ अब भी ईरान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी

अधिकारियों ने कहा कि इस वार्ता की खबर लीक होने के बाद से गुप्त कूटनीति और अधिक जटिल हो गई है। शहबाज शरीफ ने एक्स पर कहा कि पाकिस्तान पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के लिए संवाद के हर प्रयास का समर्थन करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यापक समाधान के लिए पाकिस्तान अपनी भूमिका निभाने को सम्मान की बात मानता है। कुछ घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस संदेश को अपने प्लेटफॉर्म ट्विटर पर साझा किया।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अदरबी ने कहा कि वार्ता स्थल को

लेकर अटकलों से बचना चाहिए और आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान लंबे समय से कूटनीतिक समाधान का समर्थक रहा है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने सोमवार को ट्रंप से बातचीत कर मध्यस्थता की इच्छा जताई थी।

इसी क्रम में अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के लिए अपनी 15 बिंदुओं वाली अपेक्षाएं भी पाकिस्तान के माध्यम से पहुंचाई हैं। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि आइएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकाफ के संपर्क में हैं। शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशियान से भी फोन पर बात कर तनाव घटाने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई थी।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के कार्यालय ने कहा था कि वे इस हफ्ते तमाम देशों अपने समकक्षों से बातचीत कर रहे हैं। वहीं, ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने कहा था कि किसी तरह की बातचीत नहीं चल रही, सब फूजी खबरें हैं। वहीं, रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रवक्ता जनरल अली अबुदख्लही आलियाबादी ने कहा की संपूर्ण विजय होने तक संघर्ष जारी रहेगा।

बिकी RCB, खरीदा बिड़ला ने; शेयर मार्केट में फायदा हो गया रूस के संजीव गोयनका को, 20% तक भागे शेयर



नई दिल्ली (एजेंसी)। बिकी RCB, खरीदा बिड़ला ने; शेयर मार्केट में फायदा हो गया LSG के संजीव गोयनका को, 20% तक भागे शेयर

शेयर बाजार में बुधवार को RPSG वेंचर्स के शेयरों में जबदस्त तेजी देखने को मिली। BSE पर RPSG वेंचर्स के शेयर 20% तक उछलकर दिन के उच्चतम स्तर 721 रुपये पर पहुंच गए। उछाल के पीछे का कारण IPL टीम RCB का बिकना रहा।

टीवी के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली।

यह तेजी तब देखने को मिली जब United Spirits ने अपनी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सॉल्सिडियरी Royal Challengers Bengaluru (RCB) को 16,600 करोड़ रुपये से ज्यादा में बेचने की घोषणा की। संजीव गोयनका की RPSG वेंचर्स के शेयर हल्के-पहले बंद भाव 600.75 की अपेक्षा आज यानी 25 मार्च को 660.00 पर खुले और यह 720.90 रुपये तक गए।

यानी इसमें लगभग 20 फीसद तक की तेजी देखने को मिली। Sun TV का स्टॉक BSE पर आज 5% बढ़कर 649.40 रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले सत्र में यह 618.50 रुपये पर बंद हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप 24,171 करोड़ रुपये रहा। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने नवंबर में बेंगलुरु फ्रेंचाइजी में अपनी 100% हिस्सेदारी की रणनीतिक समीक्षा शुरू की, और इस टीम को अपने मुख्य शराब कारोबार के

लिए गैर-मुख्य करार दिया।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए हुई महाद्वीपों तक फैली बोली में दुनिया भर की प्राइवेट इक्रीटी फर्म च्याक्र और Blackstone, भारतीय दिग्गज अदार पुनावाला और Manipal Education and Medical Group के चेयरमैन रंजन पई, और साथ ही Manchester United के सह-चेयरमैन Avram Glazer ने दिलचस्पी दिखाई थी। लेकिन बाजी 4 समूहों ने मिलकर मारी।

मार्च की शुरुआत में ऐसी खबरें आई थी कि संजीव गोयनका के नेतृत्व वाला RPSG रूप भी उन IPL फ्रेंचाइजी मालिकों की लीग में शामिल हो गया है, जो अपनी क्रिकेट टीमों से कमाई करना चाहते हैं। इसके तहत, रूप लखनऊ सुपर जायंट्स में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक, गोयनका 15 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहे हैं।

जीरोधा वाले नितिन कामथ की बड़ी चेतावनी, गिरावट पर बाजार में आंख मूंदकर लगा रहे हैं पैसा



नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की मशहूर ब्रोकिंग फर्म जीरोधा के को-फाउंडर नितिन कामथ ने निवेशकों को मार्केट में पैसा लगाने को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा बाजार माहौल में व्यापारियों को आक्रामक दांव लगाने से बचना चाहिए। क्योंकि, ग्लोबल मार्केट बहुत अस्थिर है और तेजी से नई-नई खबरों से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे में मुनाफा कमाने की बजाय पूंजी बचाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

लिव्कडइन पर एक पोस्ट में, कामथ ने कहा कि मौजूदा स्थिति ने ट्रेडिंग को असामान्य रूप से कठिन बना दिया है, दोनों तरफ तेज उतार-चढ़ाव के कारण पूरे विश्वास के साथ पोजीशन लेने की गुंजाइश बहुत कम रह गई है। उनके अनुसार, ऐसी परिस्थितियों में सबसे अच्छा तरीका जोखिम को काफी कम करना, एक्सपोजर को घटाना और रिटर्न के पीछे भागने के बजाय पूंजी संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है।

ट्रंप पर बरसे नितिन कामथ-

कामथ ने कहा, यह विडंबना है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एक व्यक्ति के मनमाने फैसलों पर निर्भर होता प्रतीत हो रहा है, और वह व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, और करता भी है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह सुबह किस मूड में उठता है।

मुनाफे से ज्यादा जरूरी पैसा बचाना- कामथ ने कहा कि जब बाजार स्पष्ट रूझानों या फंडामेंटल फैक्टर्स के बजाय सुर्खियों से ज्यादा प्रभावित हो रहे हों, तो व्यापारियों को अधिकतम लाभ कमाने के बजाय बाजार में बने रहने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसे बाजार में सही तरीके से आगे बढ़ने का एक सबसे व्यावहारिक तरीका है कि ट्रेड का आकार कम किया जाए और बहुत बड़ी पोजीशन लेने से बचा जाए।

किल नेटवर्क, जापान की टाइप-12 मिसाइलों की तैनाती पर क्यों बिलबिला रहा चीन?

नई दिल्ली (एजेंसी)। जापान ने दक्षिण-पश्चिमी कुमांगोटो प्रांत में कैप केगुन में अपने सतह-से-जहाज में मार करने वाली टाइप-12 मिसाइलों को तैनात करने का फैसला किया है। इस फैसले से चीन बिलबिला गया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि इस कदम से एक किल नेटवर्क बन सकता है, जो पड़ोसी देशों के तटीय और अंदरूनी दोनों तरह के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम होगा।

दरअसल पूर्वी चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच जापान ने अपनी लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइलों की क्षमता का विस्तार करने की तैयारी कर ली है। 34-श्रद्ध-12 मिसाइलें इसमें से ही एक हैं। पीएलए के मुताबिक, इनकी मारक क्षमता 200 किमी से बढ़कर 1000 किमी कर दी गई है। पीएलए की रिपोर्ट में दावा



हू आर्मी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के हुआ डैन और झांग ली ने इस पर अपनी रिपोर्ट साझा की है। इसके मुताबिक, जापान ने ऐसा करके विशिष्ट आक्रामक क्षमताएं और मजबूत स्टीथ प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट में लिखा है कि अगर इन

मिसाइलों को क्यूशू द्वीप पर तैनात किया जाता है, तो इसकी रेंज में पूरा पूर्वी चीन सागर ही नहीं, बल्कि चीन के तटीय शहर भी आएंगे। चीन को डर है कि ताइवान से संघर्ष की स्थिति में जापान इसका इस्तेमाल उसकी नौसेना को रोकने में कर सकता है।

ताइवान को लेकर तनाव

दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। उसका कहना है कि वह इसे अपने कंट्रोल में लाने के लिए बल प्रयोग भी कर सकता है। लेकिन अमेरिका और जापान ताइवान पर किसी भी बलपूर्वक कब्जा करने की नीति के खिलाफ हैं और जापान ने साफ तौर पर कहा दिया है कि अगर ताइवान पर हमला होता है, तो वह सैन्य हस्तक्षेप करेगा।

रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई है कि जापान अपनी टाइप 12 मिसाइलों को ह्युपरसॉनिक ग्लाइडिंग प्रोजेक्टाइल के साथ मिलाकर एक संयुक्त हमलावर क्षमता बना लेगा, जिसे जल्द ही तैनात किया जाएगा। जापान एक हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार को भी कैप फूजी में तैनात करने वाला है, जिसकी रेंज 500-900 किमी है और इसे बढ़ाकर 3000 किमी किया जाना है।

कौन है वो सम्मानित हस्ती जिसके साथ ईरान से जंग खत्म करने की बात कर रहा अमेरिका? रिपोर्ट में खुलासा



नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान के साथ जंग के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि अमेरिका बहुत मजबूत बातचीत कर रहा है और ईरान में सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति के साथ डील कर रहा है, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति का नाम बताने से इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा था, हम कुछ ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जो मुझे बेहद ही समझदार और भरोसेमंद लगते हैं। अंदर के लोग जानते हैं कि वे कौन हैं? वे बेहद ही सम्मानित व्यक्ति हैं और हो सकता है कि उनमें से कोई ठीक वैसा ही हो, जिसकी हमें तलाश है।

कौन है वह %सम्मानित व्यक्ति- सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ट्रंप

समक्ष खड़ी चुनौतियों को दबाने में अपनी भूमिका को लेकर कभी भी संकोच नहीं करते रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है और फाइनेंशियल तथा तेल बाजारों में हेरफेर करने और उस दलदल से निकलने के लिए फेक न्यूज का इस्तेमाल किया जा रहा है,

जिसमें अमेरिका और इजरायल फंसे हुए हैं। युद्ध शुरू होने से पहले भी गालिबाफ ने दी थी चेतावनी- पूरे संघर्ष के दौरान उन्होंने नियमित रूप से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ट्रंप को उकसाया है और युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान की शर्तों पर अपना कड़ा रुख दिखाया है।

उन्होंने 10 मार्च को एक्स पर कहा, निश्चित रूप से हम युद्धविराम की मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हमलावर को सजा मिलनी चाहिए और उसे ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए, जो उसे दोबारा ईरान पर हमला करने से रोके। युद्ध छिड़ने से पहले भी गालिबाफ एक प्रमुख हस्ती थे, जिन्होंने चेतावनी दी थी कि इस तरह का संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि शासन के प्रभाव-केंद्रों में उनके ऐसे संपर्क हैं, जो किसी भी बातचीत से होने वाले समझौते में उन्हें एक अहम भूमिका दिला सकते हैं। इस्लामी गणराज्य की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित करने के बाद गालिबाफ अब शासन के एक ऐसे माहिर व्यक्ति बन गए हैं, जो 1979 की इस्लामी क्रांति के प्रति अटूट रूप से वफादार हैं और उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के समर्थक हैं।

एयरटेल से आ गई बड़ी खबर, सुनील मित्तल इस पद से होंगे रिटायर; इन्हें मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी



नई दिल्ली (एजेंसी)। एयरटेल अफ्रीका ने बुधवार को घोषणा की कि सुनील भारतीय मित्तल जुलाई, 2026 में कंपनी की वार्षिक आम बैठक (तारु) के समापन के साथ निदेशक मंडल के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। गोपाल विट्टल को उसी तिथि से गैर-कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जबकि श्रावित भारतीय मित्तल डिप्टी चेयरमैन का पदभार संभालेंगे। श्रावित मित्तल के डिप्टी चेयरमैन का पदभार संभालने से एयरटेल अफ्रीका के संस्थापक परिवार और महत्वपूर्ण शेयरधारक के साथ निरंतरता सुनिश्चित होगी।

एयरटेल अफ्रीका 14 देशों में दूरसंचार और मोबाइल मनी सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी ने बयान में कहा, सुनील भारतीय मित्तल ने बोर्ड को सूचित किया है कि वह इस वर्ष की सालाना आम बैठक समाप्त होने के साथ जुलाई, 2026 में निदेशक मंडल (बोर्ड) के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त होना चाहते हैं। एयरटेल अफ्रीका ने कहा कि मित्तल 2019 से चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं और बोर्ड इस अवधि के दौरान उनके नेतृत्व और योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता है। कंपनी ने कहा कि विट्टल की नियुक्ति कंपनी में

नियंत्रक शेयरधारकों के नामांकन द्वारा की गई है। यह कंपनी, भारतीय एयरटेल, एयरटेल अफ्रीका मॉरीशस लिमिटेड (बहुसंख्यक शेयरधारक और भारतीय एयरटेल की एक अप्रत्यक्ष अनुषंगी कंपनी) और भारतीय एयरटेल के बीच 17 जून, 2019 को हुए संबंध समझौते की शर्तों के अनुरूप है।

विट्टल को अक्टूबर, 2024 में एयरटेल अफ्रीका का गैर-कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। बयान में कहा गया है कि श्रावित भारतीय मित्तल उसी तिथि से डिप्टी चेयरमैन का पदभार ग्रहण करेंगे। बयान के अनुसार, डिप्टी चेयरमैन के रूप में मित्तल संस्थापक परिवार और महत्वपूर्ण शेयरधारक के साथ निरंतरता सुनिश्चित करेंगे और एयरटेल मनी बोर्ड, जिसके वह सदस्य हैं और दुबई स्थित एयरटेल अफ्रीका के मुख्यालय, जहां वह रहते हैं, के साथ बोर्ड के संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करेंगे।

काशी में माँ की दया की झोली: महादेव की भिक्षा का रहस्य

नवरात्र के अष्टमी तिथि को माँ अन्नपूर्णा पूजी जाती हैं

दैनिक दिव्य संवाद/ सौरभ मिश्रा/ वाराणसी। वाराणसी में शारदीय नवरात्र के आठवें दिन को अष्टमी पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने महागौरी के रूप में अन्नपूर्णा दरबार में दर्शन पूजन किया। विश्वनाथ गली स्थित माता के दरबार में दर्शन पूजन के बाद महिलाओं और पुरुषों ने परिवार के सुख, शांति, और समृद्धि की मंगला कामना की। मंगला आरती के बाद ही श्रद्धालुओं के दर्शन शुरू हुए, जो रात्री तक चलता रहा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कतारबद्ध श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मंदिर प्रांगण में माँ के गगनभेदी जयकारे से गूंज रहा था।



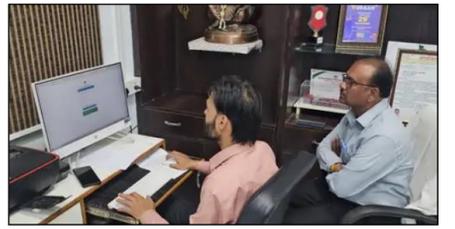
श्री अन्नपूर्णा मठ मंदिर

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट भगवती माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। मान्यता अनुसार इन्हें तीनों लोकों की माता माना जाता है। कहा जाता है की भगवती ने स्वयं भगवान शिव को भोजन कराया था। इस मंदिर में के दीवार पर बने देवी के चित्र भी बने हुए हैं। विशेषतः मंदिर प्रबंधक काशी मिश्रा ने बताया कि अन्नपूर्णा मंदिर में अन्य कई विग्रह विराजमान हैं। जिसमें मंदिर यंत्रधर स्वरूप में दीखता है धनतेरस से अन्नकूट महोत्सव तक स्वर्णमयी अन्नपूर्णा का दर्शन चार दिन होता है। भक्त माता के दर्शन हेतु देश के कोने कोने से आते हैं। मंदिर में आदि शंकराचार्य ने अन्नपूर्णा स्त्रोत की रचना कर ज्ञान वैराग्य की कामना की थी जिस प्रकार है - अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरप्राण वल्लभे। ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थ भिक्षां देहि च पावती।

जाता है। भक्त देवी का आशीर्वाद लेने और अपने जीवन में जीविका और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाते हैं।

मंदिर इतिहास- मान्यता के अनुसार उज्जैनी नरेश महाराजा विक्रमादित्य ने काशी में 12 वर्ष तक माँ भगवती की घोर आराधना की। माँ ने तपस्या से प्रसन्न हो चरण स्वरूप में माँ अन्नपूर्णा एवं मुख स्वरूप में माँ हस्तिद्वि (उज्जैन) में भक्तों पर कृपा करने का बचन दिया था। माता दरबार निर्माण- बाजीराव पेशवा ने सन 1725 में मंदिर को स्थापित किया था। माँ अन्नपूर्णा की दो फिट ऊंची वर्तमान प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा श्रेरी मठ के जगत गुरु शंकराचार्य अभिनव विद्या तीर्थ के सानिध्य में 1977 में की गई। पहुंचने कैसे- वाराणसी पहुंच कर गोदौलिया दशरथमेष, बांस फाटक और ज्ञानवापी चौक से मंदिर पहुंचा जा सकता है। माँ के दर्शन मात्र से धन धान्य भरा होता है- मंदिर के महंत शंकर पुरी ने बताया कि शरद अष्टमी के दिन माँ गौरी के रूप में दर्शन देती हैं। माँ का हरियाली श्रृंगार धूम-धाम से मनाया जाता है। इसके बाद महिलाएं व पुरुष 17 दिवसीय महाव्रत करते हैं। माँ का वर्ष में चार दिवसीय स्वर्णमयी प्रतिमा का दर्शन व अनुष्ठान भी होता है। माँ के दर्शन पूजन से परिवार में सुख, शान्ति और समृद्धि बनी रहती है।

5वीं में 28वीं 8वीं में रही 31वीं रैंक



शाजापुर। राज्य शिक्षा केंद्र ने बुधवार को कक्षा 5वीं और 8वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किए। इसमें शाजापुर जिले ने प्रदेश स्तर पर सराहनीय प्रदर्शन किया है। जिले ने दोनों कक्षाओं में प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान बनाया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस सफलता को विद्यार्थियों और शिक्षकों के साझा प्रयासों का परिणाम बताया है। कक्षा 5वीं की परीक्षा में शाजापुर जिले ने प्रदेश में 28वीं रैंक हासिल की है। इस परीक्षा में कुल 15 हजार 664 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 15 हजार 11 छात्र-छात्राओं ने सफलता प्राप्त की। जिले का कुल परीक्षा परिणाम 95.86 प्रतिशत दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर है। इसी प्रकार कक्षा 8वीं के परिणामों में शाजापुर जिला प्रदेश में 31वें स्थान पर रहा। जिले में कुल 13 हजार 997 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 13 हजार 168 विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए। इस कक्षा का कुल पास प्रतिशत 94.8 रहा है। बोर्ड पैटर्न से बड़ा प्रतिस्पर्धा का स्तर- जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शिप्रे ने बताया कि पिछले तीन वर्षों से 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की जा रही हैं।

कलेक्टर ने ऑयल कंपनियों के विक्रय अधिकारियों की बैठक ली

देवास। कलेक्टर ऋगुराज सिंह ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में जिले में पेट्रोल/डीजल की नियमित आपूर्ति बनाये रखने के संबंध में ऑयल कंपनियों के विक्रय अधिकारियों की बैठक ली गई। कलेक्टर सिंह ने सभी आईल कंपनियों के विक्रय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में सभी पेट्रोल/डीजल पम्पों पर ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा जिला प्रशासन से समन्वय कर नियमित रूप से वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी देवास को निर्देश दिए कि सभी पेट्रोल/डीजल पम्पों पर वितरण व्यवस्था पर निगरानी रखी जाए तथा पेट्रोल/डीजल की कालाबाजारी/जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाए। कलेक्टर सिंह ने जिले के समस्त उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि जिले में



पेट्रोल/डीजल एवं गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी प्रकार की घबराहट में अनावश्यक पेट्रोल/डीजल की खरीददारी करने की आवश्यकता नहीं है। बैठक में विक्रय अधिकारी आईओसीएल कौषलेन्द्र यादव ने बताया कि कंपनी द्वारा डिंपो से पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति सतत रूप

से की जा रही है। आईओसीएल द्वारा आगामी दिवसों में डिंपो से 24 घंटे पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति किये जाने के संबंध में भी विचार किया जा रहा है। विक्रय अधिकारी बीपीसीएल मेहफूज खान ने बताया कि डिंपो से पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति जारी है। जिले में सभी आईल कंपनियों के कुल 186 पेट्रोल/डीजल पम्प संचालित हैं, जिनमें से 23 पम्प संचालकों द्वारा राईश जमा नहीं करने पर पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति बाधित हुई है, शेष सभी पम्पों पर संबंधित आईल कंपनियों द्वारा नियमित रूप से पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति की जा रही है। दिनांक 25 मार्च 2026 की स्थिति में जिले के सभी पेट्रोल/डीजल पम्पों पर कुल पेट्रोल 730 के.एल. डीजल 1287 के.एल तथा पावर पेट्रोल 234 के.एल उपलब्ध है। जिले में किसी भी क्षेत्र में पेट्रोल/डीजल के अनुपलब्धता की स्थिति नहीं है।

ड्रस कारोबार पर सख्ती की मांग, विहिप-बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

नीमच। जिले में बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ विहिप हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने बुधवार को कलेक्टर व एसपी के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रखंड अध्यक्ष बंटी अग्रवाल और प्रखंड मंत्री नितिन बागड़ी ने बताया कि जिले में एमडी ड्रस का कारोबार तेजी से फैल रहा है। खारी कुआं, मूलचंद मार्ग, बघाना और मनासा क्षेत्र में नशे की उपलब्धता बढ़ने से युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 22 मार्च 2026 को एक 25 वर्षीय युवक की मौत के मामले में एमडी ड्रस सेवन की बात



सामने आई है, जो चिंता का विषय है। संगठन ने आरोप लगाया कि ड्रस पेडलर युवाओं को नशे की लत में धकेल रहे हैं, जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि एमडी ड्रस और अन्य नशीले

पदार्थों के कारोबार में शामिल गिरोहों की व्यापक जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाकर इस पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान लक्ष्मण राठौर, सत्यनारायण पाटीदार, संजय यादव, कैलाश मालवीय, दिनेश शर्मा, विनोद जायसवार, दिलीप ग्वाला, राम अवंतार शर्मा, पवन जायसवार, संजय चौरसिया, सूरज ग्वाला, अरविंद रावत, गोतम बैरागी, रोशन वर्मा, किशन नंदानी, विशाल ग्वाला, पवन पुरोहित, अजय बारसे, राजेश बंदी, लक्ष्मण सेन, राजू धनगर, बाबूलाल धाकड़, रवि परिहार, अमन मराठा, दशरथ भील, विक्रम माली, कार्तिक माली, गोविंदा भील सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

“अब नहीं मिलेगा पेट्रोल” सुनते ही पंप की ओर दौड़े नगरवासी

शाजापुर। कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे नगरवासी अब पेट्रोल की किल्लत की अफवाह से परेशान हैं। किसी ने पेट्रोल न मिलने की अफवाह फैला दी, जिसके चलते मंगलवार देर रात तक पंप पर सैकड़ों लोग टिकियां फूल करवाने पहुंच गए। हालांकि जिला प्रशासन ने साफ किया कि कोई किल्लत नहीं है। इसके बाद भी बुधवार सुबह से लोग पंप पर पहुंच गए। मंगलवार को किसी ने अफवाह फैला दी कि पेट्रोल खत्म होने वाला है। यह सुनते ही लोगों ने बिना जांच किए अपने वाहन स्टार्ट किए और पंप की ओर दौड़े और जरूरत न होने पर भी पेट्रोल लेने लगे। जिसके चलते रात में ही नगर के दो पेट्रोल पंप पर सफाई बंद कर दी गई थी। जबकि एक पेट्रोल पंप पर सफाई की जा रही थी। यही हाल बुधवार को भी रहे और बुधवार को भी नगर के पेट्रोल



पंप पर लोग पेट्रोल के लिए परेशान होते रहे। जबकि अधिकारियों की माने तो नगर में डीजल या पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है। बावजूद इसके लोग अफवाह के कारण इधर-उधर वाहन दौड़ाते रहे। यही नहीं कई लोगों ने तो अतिरिक्त स्टॉक भी कर लिया। कई लोग कैश और बड़ी बाटलें लेकर उनमें पेट्रोल लेते नजर आए। कलेक्टर ने की अपील, अफवाहों न दें ध्यान- रात में पंपों पर लगी लोगों की भीड़, अफवाह और स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने रात ही में लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। जिले

में डीजल, पेट्रोल व घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने जिले के नागरिकों एवं उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिले में मांग के अनुसार डीजल, पेट्रोल एवं गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है तथा सभी पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसियों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। पेट्रोलपंप संचालकों को विभाग की ओर से निर्देशित किया गया है कि पेट्रोल पंप में स्टॉक और विक्रय की स्थिति को देखते हुए ऑयल कंपनी से अग्रिम रूप से फ्यूल की मांग कर उपभोक्ताओं को सफाई व्यवस्था सुचारु रूप जारी रखे। जिला प्रशासन एवं जिला आपूर्ति अधिकारी ने नागरिकों से आग्रह किया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें एवं आवश्यकतानुसार ही ईंधन एवं गैस का क्रय करें, ताकि सभी उपभोक्ताओं को सुचारु रूप से उपलब्धता बनी रहे।

सभी अधिकारी प्रशिक्षण अच्छी तरह से प्राप्त कर त्रुटिरहित कार्य संपादित करें- कलेक्टर

शाजापुर। प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं कलेक्टर सुश्री ऋजू बाफना की अध्यक्षता में आज जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए चार्जवार नामित फिल्ड ट्रेनर्स तीन दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर सुश्री ऋजू बाफना ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी जनगणना-2027 का प्रशिक्षण अच्छी तरह से प्राप्त कर त्रुटिरहित

कार्य संपादित करें। साथ ही आपसी समन्वय से कार्य करते हुए समय-सीमा के भीतर प्रशिक्षण, संसाधन प्रबंधन, तकनीकी समन्वय एवं मैदानी अवलोकन की तैयारी पूर्ण करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि चार्ज अधिकारी मैदानी अवलोकन के माध्यम से कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से संपादित कराएं तथा प्रशिक्षण, जनजागरूकता एवं अन्य सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने उपस्थित सभी से

उक्त प्रशिक्षण को अच्छी तरीके से प्राप्त करने के लिए कहा। प्रथम दिवस प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स भोपाल से आई सुश्री साक्षी कुमावत व डॉ. वीपी मीणा द्वारा दिया गया। जिसमें स्व-गणना, HLO-SE पोर्टल, मकानसूचीकरण ब्लॉक (HLB) के गठन, भू-स्थान मैपिंग, भवन क्रमांकन, डेटा सत्यापन एवं मैदानी कार्यप्रणाली आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर जिले के प्रभारी श्री

मिलिन्द देशपाण्डे, अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर सुश्री मनीषा वास्करले, शुजालपुर श्री राजकुमार हलदर, गुलाना सुश्री नेहा गंगारे, डिप्टी कलेक्टर श्री आलोक वर्मा व श्रीमती अंकिता पाटकर सहित जिला सूचना विज्ञान अधिकारी तथा चार्ज स्तर पर ग्रामीण चार्ज अधिकारी, अतिरिक्त चार्ज अधिकारी, नगरीय - नगरपालिका/ नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं समस्त फील्ड ट्रेनर्स उपस्थित थे।

राजीनामा भी डकार गए और 5 लाख भी, अब रजिस्ट्री वाली जमीन पर कब्जा कर फिर मांग रहे रुपये

नीमच। जिले के ग्राम चीताखेड़ा में जमीन की खरीद-फरोख्त के बाद एक अजीब मामला सामने आया है जहां रजिस्ट्री और लिखित राजीनामे के बावजूद पीड़ित अपनी ही जमीन के लिए दर-दर भटक रहा है। कनावटी निवासी राजेश बैरागी की खरीदी हुई जमीन और उस पर बने बाड़े पर गांव के ही राजेश साल्वी और उसके साथियों ने अवैध कब्जा कर लिया है। अब कब्जा छोड़ने के बदले फिर से रुपयों की मांग की जा रही है और मना करने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लिखित समझौता कर डकारे 5 लाख, अब फिर जागा लालच- पूरा विवाद जमीन के मालिकाना हक और कब्जे को लेकर है। पीड़ित राजेश बैरागी ने साल 2023 में चीताखेड़ा में सर्वे नंबर 1503/2 और 1503/3 की कृषि भूमि चांदमल साल्वी



से कानूनन रजिस्ट्री करवाकर खरीदी थी। राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़ने के बाद भी विक्रेता के भाई राजेश साल्वी और उसके साथियों ने विवाद खड़ा कर दिया। मामला सुलझाने के लिए गांव के लोगों के बीच लिखित समझौता हुआ था। समझौते के तहत राजेश साल्वी और उसके पक्ष ने 5 लाख रुपये नकद लिए और दूसरी जगह बाड़ा भी बनवा लिया। लेकिन रुपया और नया बाड़ा हाथ में आते ही आरोपी राजीनामे से पलट गए और फिर से पुरानी जमीन पर

कब्जा कर लिया। पुलिस केस के बाद भी बेखोफ, रास्ते में रोककर दी धमकी- जमीन के लालच में आरोपी इस कदर बेखोफ हैं कि उन्होंने 8 मार्च 2026 को पीड़ित का रास्ता रोककर गाली-गालौज की। राजेश बैरागी ने बताया कि जब वह अपने खेत पर जा रहे थे, तब आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद पुलिस ने एकआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन धरातल पर अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपियों का हौसला इतना बढ़ा हुआ है कि वे अब पीड़ित को ही झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर दबाव बना रहे हैं। कलेक्टर और एसपी से लगाई न्याय की गुहार- सिस्टम की सुस्ती और पुलिस की ढिलाई के कारण पीड़ित अब दफतरो के चक्र काटने को मजबूर है। राजेश बैरागी

ने कलेक्टर और एसपी को शिकायती आवेदन देकर अपनी जान-माल की सुरक्षा मांगी है। पीड़ित का कहना है कि जब रजिस्ट्री उसके नाम है और राजीनामा भी हो चुका है, तो फिर प्रशासन अवैध कब्जा क्यों नहीं हटवा रहा है। गांव में चर्चा है कि अगर कानूनी कागजों और पंचायत के फैसलों की ऐसी ही धज्जियां उड़ेंगी, तो आम आदमी जमीन खरीदने से पहले सौ बार डरेगा। क्या प्रशासन दिला पाएगा अपनी जमीन पर हक- फिलहाल पीड़ित ने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त आपराधिक केस दर्ज किया जाए और उसके बाड़े से अवैध कब्जा हटाया जाए। बड़ा सवाल यह है कि जब 6 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांव के बीचों-बीच ऐसा विवाद चल रहा है। ऐसे में राजस्व और पुलिस विभाग को इस ओर ध्यान आकर्षित कर जमीन से कब्जा हटवाना के मांग है।

उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने 11 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया, ऑडिटोरियम भी शामिल

मंदसौर। मल्हारगढ़ जनपद पंचायत परिसर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा लगभग 11 करोड़ रुपये के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया। इस अवसर पर ग्राम डिक्रिया में 37 लाख 50 हजार रुपये की लागत से निर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण किया गया, वहीं 10 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से बनने वाले 42 मांगलिक भवनों का भूमिपूजन किया गया। ये सभी भवन मल्हारगढ़ जनपद की 42 अलग-अलग ग्राम पंचायतों में निर्मित होंगे। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, जिला योजना समिति सदस्य राजेश दीक्षित, जनपद



पंचायत अध्यक्ष पुष्पा कश्यपलाल पाटीदार, मदन लाल राठौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सरपंच, नागरिक एवं पत्रकार उपस्थित रहे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों की सतत निगरानी की जाए और गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि शासकीय राशि को अपनी राशि समझकर कार्य करें

और सभी मांगलिक भवन निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि जनता ने सेवा का अवसर दिया है, जिसके लिए वे आभारी हैं। उन्होंने जानकारी दी कि 42 मांगलिक भवनों के अतिरिक्त 60 और भवन स्वीकृत किए गए हैं, जिनका निर्माण लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इसके अलावा मल्हारगढ़ एवं पिपलिया मंडी में फ्लाईओवर निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होंगे। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2026 तक गांधी सागर परियोजना का पानी हर खेत तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जिससे सिंचाई सुविधा में विस्तार होगा।